● वर्ष-4
● अंक-136
रायपुर, शुक्रवार
17 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» हमें सुबह में ही गहरी नींद क्यों आती है?

पूजा स्थल कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस ...

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें उसने 1991 के उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध किया। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप को वैसे ही बनाए रखता है, जैसा वे 15 अगस्त 1947 को थे। विपक्षी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) में दखल देने का आग्रह किया। याचिका में उपाध्याय ने इस कानून की संविधानिक वैधता को चुनौती दी है।

याचिका में कांग्रेस ने कहा कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए जरूरी है और इस पर उठाए गए सवाल जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास प्रतीत होते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के स्थापित सिद्धातों को कमजोर करने के लिए गए हैं। पार्टी ने कहा कि उसे आशंका है कि अगर इस कानून में कोई बदलाव हुआ, तो इससे भारत में सांप्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता को खतरा पैदा हो सकता है, जो देश की

संप्रभुता और अखंडता को भी खतरे में डाल सकता है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और इस कानून को पारित करने में उसका अहम योगदान था, जब वह और जनता दल पार्टी लोकसभा में बहुमत में थे। पार्टी ने आगे कहा कि वह अपने निर्वाचित सदस्यों के जरिए उपासना स्थल कानून को पारिर करने के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उसे इस मामले में दखल देने की अनुमति मिलनी चाहिए और उपासना स्थल कानून की वैधता का बचाव किया जाना चाहिए।

विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपाध्याय ने संदिग्ध और गोपनीय उद्देश्यों से याचिका दायर की है। याचिका में यह गलत दावा किया गया है कि उपासना स्थल कानून केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार सभी धर्मों के समुदायों के पूजा स्थलों पर समान रूप से लागू होता है और यह 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति को सुनिश्चित करता है, न कि किसी विशेष समुदाय के प्रति पक्षपात, जैसा कि दावा किया गया है।

उपासना स्थल कानून पर क्या विवाद है?

देश की संसद ने 18 सितंबर 1991 को उपासना स्थल अधिनियम, 1991 (अधिनियम) पारित किया था। उपासना स्थल कानून में सात धाराएं हैं। शुरुआती खंड में कानून का उद्देश्य किसी भी उपासना स्थल के बदलाव पर रोक लगाना और किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 के अनुसार बनाए रखना बताया गया है। यह अधिनियम उस समय चुनौती के दायरे में आया जब सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या स्थित विवादित ढांचे के मसले का फैसला कर रहा था। 9 नवंबर 2019 को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित संपत्ति का मालिकाना हक श्री रामलला विराजमान को दिया। इस फैसले ने 450 साल पुराने विवाद की फाइलें बंद कर दीं। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता को बरकरार रखा।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें दावा किया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय, पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, धर्मगुरु स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती और देवकीनंदन ठाकुर, काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की बेटी कुमारी कृष्णा प्रिया और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल कबोत्रा शामिल हैं।

18 नक्सलियों को मार गिराया

बीजापुर में मुठभेड़; गोलीबारी जारी

बीजापुर। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर व मारुड़बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में सुरक्षाबल के जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर तीन जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दक्षिण बीजापुर के जंगल में सुबह करीब नौ बजे गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारी ने कहा कि रुक-रुककर गोलीबारी अभी भी जारी है, आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

बताया जाता है कि नक्सली बड़ी बैठक ले रहे थे। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कैडर के हार्ड कोर नक्सली बैठक में शामिल थे। इनामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। पुलिस ने सूचना के आधार पर ये एनकाउंटर किया है।

घना जंगल होने की वजह से नक्सली भाग नहीं पाये। सभी जवान सुरक्षित बताये जा रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस फोर्स के वापस लौटने के बाद की पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि कुल कितने नक्सली मारे गये हैं। जवान नक्सलियों के शवों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद इन शवों की शिनाख्ती की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस नक्सल ऑपरेशन में करीब एक हजार जवान शामिल हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। इससे हड़बड़ाये नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवान मोर्चा संभाल कर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के भारी नुकसान की बात कही जा रही है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज इस नक्सल ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन जिलों के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के कर्मी, सीआरपीएफ की विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन) की पांच बटालियन और सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन ऑपरेशन में शामिल हैं। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में दो महिलाओं समेत पांच नक्सली मारे गये थे।

पुलिस ने कहा था कि दो साल में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों पर अपने सबसे बड़े हमले में नक्सलियों ने इस महीने की शुरुआत में बीजापुर जिले में 60 से 70 किलोग्राम वजन वाले एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके एक वाहन को उड़ा दिया, जिसमें आठ सुरक्षाकर्मी और उनके नागरिक चालक की मौत हो गई।

अर्बन नक्सल्स के चंगुल में हैं राहुल गांधी : रविशंकर

नईदिल्ली। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहरी नक्सलियों की सोच प्रक्रिया की पूरी तरह से पकड़ में हैं, और पूछा कि क्या उन्हें अब हिंडनबर्ग रिसर्च की बंद दुकान का अनुबंध मिल गया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी गांधी की उनकी टिप्पणियों के लिए आलोचना की कि कांग्रेस अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रही है, और कहा कि भारतीय राज्य एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत की संवैधानिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कल बोले किराहुल गांधी जी आप संसद में विपक्ष के नेता हैं और आप भारतीय राज्य से लड़ने की बात कर रहे हैं! भारतीय राज्य भारत के संवैधानिक व्यक्तित्व का परिचय है। राहुल गांधी को बोलने से पहले समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी दुकान बंद कर दी है। इसे बंद क्यों किया गया है? हाल ही में इसके संस्थापक जॉर्ज सोरोस को स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। जाहिर है अमेरिकी में सोरोस की दुकान या तो बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है।

प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने वाले नए प्रशासन के साथ अमेरिका स्थित अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की %दुकान% भी बंद होने जा रही है। उन्होंने कहा, सोरोस हिंडनबर्ग को फंड देता है। हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य से अरबों डॉलर का सफाया करने वाले अरबपति गौतम अडानी को लक्षित अभियानों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई, वह भंग हो जाएगी, इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने गुरुवार को घोषणा की। 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत करने वाले 40 वर्षीय एंडरसन की घोषणा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के उद्घाटन से कुछ दिन पहले आई थी।

वाहन चलाते समय यातायात नियमों का करें अवश्य पालन: सीएम साय

रायपुर। प्रदेश में मनाये जा रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाईक चलाते हुए प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने और यातायात के नियमों के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर के रोहणीपुरम गोल चौक पहुँचकर बाईक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ चार पहिया वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान श्री साय ने हरी झण्डी दिखाकर भव्य बाईक रैली को रवाना भी किया। रैली के दौरान स्वंयसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया।

प्रमुख समाचार

आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर ही लड़ पाएंगे चुनाव

नईदिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कोई व्यक्ति तभी सरपंच, नगर निगम पार्षद या मेयर बन सकता है, जब उसके दो से अधिक बच्चे हों, यह संकेत देते हुए कि यह गिरती जनसंख्या को रोक देगा। नायडू ने कहा कि वह लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए

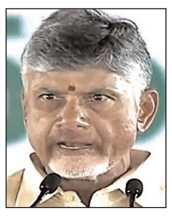

प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लाएंगे। उन्होंने कहा कि एक समय में, कई बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत (चुनाव) या स्थानीय निकायों में लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि कम बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सरपंच, नगर निगम पार्षद, निगम अध्यक्ष या महापौर तभी बन पाएंगे जब आपके दो से अधिक बच्चे होंगे। सीएम के अनुसार, उत्तर भारत लगभग 15 वर्षों में स्थिर प्रजनन दर का लाभ खो सकता है। उन्होंने कहा, आपके माता-पिता चार से पांच बच्चे पैदा करते थे और आपने इसे घटाकर एक कर दिया। यहां तक ??कि होशियार लोग भी अब कह रहे हैं कि दोगुनी आय वाले बच्चे हमें आनंद नहीं लेने देते। अगर उनके माता-पिता ने उनके जैसा सोचा होता।

13 फरवरी को होगी गोधरा कांड पर सुप्रीम सुनवाई

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर अपील पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि सुनवाई की अगली तारीख पर

मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को जलाए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे राज्य में दंगे भड़क उठे थे। गुजरात उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई अपीलें दायर की गई हैं, जिसने कई दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए आया, तो एक दोषी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि हमें पता नहीं। हम मामले की सुनवाई करेंगे और हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था। हम इस मामले को स्थगित नहीं करेंगे।

फिर जोर पकड़ेगा किसान आंदोलन! शुरू करेंगे दिल्ली मार्च

नईदिल्ली। अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 111 किसानों द्वारा खनौरी सीमा के हरियाणा की ओर आमरण अनशन शुरू करने के एक दिन बाद, 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू

करने के लिए तैयार है। उनका उद्देश्य केंद्र सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना है। किसान नेता और किसान मजदूर मोर्चा के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 101 किसानों के समूह ने पिछले साल 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर को शम्भू सीमा से दिल्ली तक मार्च करने के तीन प्रयास किए थे। हालाँकि, इन प्रयासों को हरियाणा पुलिस ने विफल कर दिया। पंधेर ने किसानों के निरंतर विरोध के बावजूद उनकी मांगों को संबोधित करने से इनकार करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोनों मंचों एसकेएम और केएमएम ने फैसला किया है कि 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा।

प्रशांत किशोर ने तोड़ा अनशन, गंगा में लगाई डुबकी

नईदिल्ली। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद गुरुवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। किशोर पिछले महीने आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में 2

जनवरी से आमरण अनशन पर थे। किशोर अपने सत्याग्रह आंदोलन के अगले चरण की भी शुरुआत करेंगे। अपना उपवास तोड़ने से पहले, किशोर ने पटना में गंगा पथ के पास पवित्र नदी गंगा में प्रतीकात्मक डुबकी लगाई, जो उनके विरोध में एक महत्वपूर्ण क्षण था। किशोर ने कहा कि ये कोई रैली या विरोध प्रदर्शन नहीं है। पिछले 14 दिनों से जन सुराज परिवार की ओर से मैंने प्रयास किया है कि छात्रों को न्याय मिले। यह लड़ाई प्रशांत किशोर ने शुरू नहीं की; इस संघर्ष की शुरुआत बिहार के उन छात्रों ने की थी जिनका मानना है कि बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं। किशोर ने कहा कि वह बिहार सत्याग्रह आश्रम नाम से एक नया मंच स्थापित करके सत्याग्रह शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, यह स्थान सभी उत्पीड़ित लोगों के लिए एक आवाज के रूप में काम करेगा,।

बजट से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी कर्मचारी संगठन इस संबंध में %टर्म आफ रेफरेंस% का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के

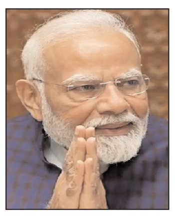

महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, सरकार को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा। अभी 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। मतलब, अगले वर्ष से वेतनमान रिवाइज होंगे। तब तक संभव है कि डीए की दर 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए। अभी तक सरकार %डॉ. एक्राय्ड% फॉर्मूले के आधार पर वेतनमान रिवाइज करती रही है। श्रीकुमार के मुताबिक, सरकार को अब इस फार्मूले से आगे बढ़ना होगा। आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। अगर आठवां वेतन आयोग %डॉ. एक्राय्ड% फॉर्मूले से आगे बढ़कर अपनी सिफारिशें देता है तो देश में न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये से बढ़कर 40000 रुपये हो सकता है।

सैन्य ताकत में रूस के बराबर पहुंचा चीन, भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश

कीर्तिवर्धन मिश्र

दुनियाभर में देशों की सैन्य ताकत परखने वाली संस्था ग्लोबल फायरपावर ने 2025 में एक बार फिर अलग-अलग देशों की ताकत से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। 60 अलग-अलग मानकों पर देशों की ताकत को परखने वाली इस संस्था ने जो रैंकिंग जारी की है, अमेरिका को मौजूदा समय में भी सबसे ताकतवर सैन्य ताकत करार दिया है। वहीं, इस रैंकिंग में रूस दूसरे नंबर पर और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इन तीनों महाशक्तियों के बाद भारत का नंबर आता है, जिसे सैन्य मामलों में चौथा सबसे शक्तिशाली देश करार दिया गया है।

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स (जीएफपी) में किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर होती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है, उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। यानी 0.0000 का स्कोर सबसे शानदार माना जाता है। इसके बाद जैसे-जैसे यह स्कोर बढ़ता रहता है, वैसे ही देशों की ताकत कम मानी जाने लगती है। इन देशों को यह स्कोर उनकी सेनाओं के संख्याबल, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक्स लाने-ले जाने की क्षमताएं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के आधार पर दिया जाता है।

ताजा स्कोर को देखा जाए तो टॉप-6 देशों की रैंकिंग 2024 की तरह ही रही है। हालांकि, सभी देशों की सैन्य ताकत के स्कोर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका टॉप पर होने के बावजूद अपने पिछले स्कोर से पीछे है। वहीं, रूस की ताकत में भी गिरावट देखी गई है। इस बीच रूस और चीन की ताकत को इस रैंकिंग में बराबर दिखाया गया है। यानी चीन की सेना की ताकत कम जरूर हुई है, लेकिन रूस की ताकत में आई कमी इतनी ज्यादा है कि दोनों के अंक अब समान हैं। इसी तरह भारत भी पहले की तरह ही लगातार चीन के बाद चौथे स्थान पर बना हुआ है। कई मानकों में दोनों देश रैंकिंग में भी एक-दूसरे से आगे-पीछे ही हैं।

टॉप-10 देशों में से छह देश एशिया के

देशों की सैन्य ताकत को अगर एशिया तक ही सीमित कर दिया जाए तो सामने आता है कि वैश्विक लिस्ट में टॉप-10 देशों में से छह देश एशिया के ही हैं। इनमें रूस सबसे ज्यादा ताकतवर है, वहीं चीन उसके बराबर के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर भारत है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान और तुर्किये का स्थान आता है। वहीं, दुनिया के शक्तिशाली देशों में टॉप-10 से बाहर हो चुके पाकिस्तान की एशिया में रैंक 7वीं हैं। उसके बाद इंडोनेशिया (स्कोर- 0.2557), इस्राइल (0.2661) और ईरान (0.3048) क्रमशः 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर हैं। एशिया में 11वें नंबर पर सबसे ताकतवर ताइवान है, जो कि चीन के खतरे को भांपते हुए लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। लिस्ट में उसे 0.3988 का स्कोर दिया गया है।

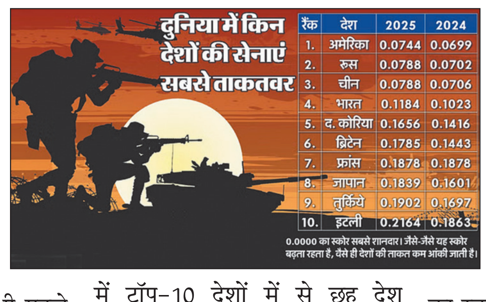

रैंक	देश	2025	2024
1.	अमेरिका	0.0744	0.0699
2.	रूस	0.0788	0.0702
3.	चीन	0.0788	0.0706
4.	भारत	0.1184	0.1023
5.	द. कोरिया	0.1656	0.1416
6.	ब्रिटेन	0.1785	0.1443
7.	फ्रांस	0.1878	0.1878
8.	जापान	0.1839	0.1601
9.	तुर्किये	0.1902	0.1697
10.	इटली	0.2164	0.1863

पाकिस्तान टॉप-10 से बाहर

दूसरी तरफ लिस्ट में फ्रांस ने फिर जगह बनाई है। 2024 में यह देश सैन्य ताकत के मामले में 11वें नंबर पर था। पिछले एक साल में फ्रांस की सैन्य ताकत में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, यानी उसका 2024 और 2025 का आंकड़ा बराबर है। इसके चलते जहां बाकी देशों की सैन्य ताकत का स्कोर कम हुआ है, वहीं फ्रांस ने एक बार फिर टॉप-10 में जगह बना ली है। यह देश सैन्य शक्ति में दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश है।

इसके अलावा फ्रांस की एंट्री के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया है। पिछले साल वैश्विक ताकत के मामले में 0.1711 के स्कोर के साथ पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। हालांकि, इस बार उसका स्कोर 0.2513 रहा, जिसके चलते वह इस लिस्ट में 12वें स्थान पर खिसक गया। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की ताकत में भी 2024 (स्कोर- 0.1944) के मुकाबले गिरावट आई है। लेकिन 0.2415 के स्कोर के साथ वह लिस्ट में पाकिस्तान से आगे 11वें स्थान पर है।

चीन से तुलना

ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग में भारत और चीन के बीच सिर्फ एक स्थान का अंतर है। जहां चीन तीसरे नंबर पर है, वहीं भारत को चौथा स्थान मिला है। हालांकि, इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में फर्क काफी ज्यादा है।

आबादी, सेना में लड़ने के लिए उपलब्ध मैनपावर, सेनाओं में सेवा देने के लिए उपयुक्त लोगों की संख्या और सक्रिय सैन्यकर्मियों में दुनिया में चीन पहले स्थान पर है। इन तीनों ही मानकों में भारत दूसरे नंबर पर है।

हालांकि, रिजर्व सैन्यबलों और अर्धसैनिक बलों की संख्या के मामले में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। दूसरी तरफ चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले करीब 3.5 गुना है।

थल, वायु और नौसेना के मामले में भी चीन अधिकतर मानकों में भारत से आगे है, फिर चाहे वह एयरक्राफ्ट की बात हो या टैंकों की। नौसैन्य क्षेत्र में चीन ने भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। उसके पास युद्धपोतों से लेकर सबमरीन तक, सबकी संख्या ज्यादा है।

पंचायत चुनाव के पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद शुरू

■ बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पंचायत चुनाव के पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गौरेला जनपद के पकरिया ग्राम पंचायत के कई ग्रामीणों ने एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ कार्यालय पहुंचकर उनका नाम काटने की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पंचायत सचिव पर फर्जी आवेदन पत्र लेकर मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने पूरे मामले पर जांच अधिकारी नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। इसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना एवं उसके बाद सूचियो का प्रकाशन शामिल है। इसी क्रम में गौरेला जनपद के पकरिया ग्राम पंचायत में मतदाता सूची के प्रथम प्रकाशन के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। ग्राम पंचायत के कई वार्ड के मतदाताओं का नाम या तो दूसरे वार्डों में जोड़ दिया गया या हटा दिया गया। इसके बाद पहले ग्राम पंचायत में विवाद हुआ।

विवाद बढ़ा तो पूरा मामला जनपद और एसडीएम तक पहुंचा। ग्राम पंचायत की महिला पुरुषों सहित लगभग दो दर्जन लोग एसडीएम कार्यालय एवं जनपद सीईओ के पास पहुंचकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनका नाम उनके पूर्व वार्डो से हटाने या विलोपित करने का आरोप पंचायत सचिव पर लगाया। जनपद सीईओ के कार्यालय में मौजूद ग्राम पंचायत पकरिया के सचिव पर आक्रोशित महिलाएं बरस पड़ीं। उन्होंने न सिर्फ उनका नाम हटाने के लिए उसे लताड़ लगाई, बल्कि नाम हटाने के लिए उनके द्वारा किए गए आवेदन की को सार्वजनिक करने की मांग की।

दरअसल नियमानुसार यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाना या संशोधन किया जाना है तो बीएलओ के पास उसका आवेदन होना आवश्यक है। आवेदन के परीक्षण के बाद ही सूची में जोड़ना, हटाना या संशोधन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार किसी ने साजिश करते हुए लगभग 50 लोगों के फर्जी आवेदन पत्र सचिव के पास पहुंचा दिए। सचिव ने भी उनका परीक्षण किए बगैर उसे सीधे बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची संशोधन टीम तक पहुंचा दिया और सभी का संशोधन हो गया। उसके बाद जब सूची का प्रकाशन हुआ तब विवाद हुआ। हालांकि पूरे मामले पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम का कहना है कि मामला गंभीर है, इसलिए पूरे मामले पर करारोपण अधिकारी को जांच अधिकारी बनकर रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में जो भी दोषी होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

ओबीसी आरक्षण पर घमासान मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मनेंद्रगढ़ तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जिले भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने धरने का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी समुदाय के आरक्षण को लगातार नजरअंदाज कर रही है। अशोक श्रीवास्तव ने कहा भाजपा सरकार पंचायत निर्वाचन में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे जिला पंचायत में एक भी जनपद पंचायत का पद ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। यह सरकार की ओबीसी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ हुए इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।

मालिक से बदला लेने ड्राइवर की खतरनाक साजिश

■ कवर्धा पुलिस अब फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक सनकी ड्राइवर ने मालिक से बदला लेने के लिए खतरनाक प्लान बनाया. ड्राइवर ने अपने मालिक का ट्रक चुरा लिया और दूसरे राज्य ले जाकर खपाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ सीमा पार करने से पहले ही नाकेबंदी कर रोक लिया। पुलिस से घिरता देख ड्राइवर गाड़ी से कूद कर जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है।

मामला कवर्धा सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत समनापुर गांव का है। जहां मंगलवार -बुधवार दरमियानी रात हाइवा मालिक विजय पटेल के घर के बाहर खड़ी उसकी हाइवा गायब थी। विजय पटेल ने जब देखा तो उसे लगा कि गाड़ी ड्राइवर लेकर गया होगा। लेकिन जब दोपहर तक गाड़ी और ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं चला तो मालिक विजय पटेल ने ड्राइवर को फोन किया। लेकिन ड्राइवर का नंबर लगातार बंद आ रहा था।

गाड़ी मालिक को काफी देर बात ख्याल आया कि ट्रक की चाबी तो घर पर ही रखी है। फिर बिना चाबी लगाए ट्रक को ड्राइवर कैसे चलाएगा। फिर ड्राइवर और ट्रक की तलाश करने पर ना ड्राइवर का कुछ पता चला ना ट्रक का। तब मालिक को चोरी की आशंका हुई और उसने कोतवाली थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया।

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गंभीरता दिखाई और फौरन खोजबीन शुरू किया। कवर्धा जिले और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ट्रक का नंबर और चेचिस नंबर सर्कुलेट किया गया। बुधवार रात सूचना मिली की चोरी ट्रक बोड़ला को पार कर मध्यप्रदेश की ओर जा रहा है।

सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल ट्रक के पीछे रवाना हुई और रास्ते में नाकेबंदी कराई गई। छत्तीसगढ़ सीमा को पार करने से पहले पुलिस ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में बंजारी के पास ट्रक को घेर लिया। पुलिस से घिरा देख ड्राइवर ट्रक छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। रात में अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया।

कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा

हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया।

वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई। इसमें अप्राकृतिक मौत कभी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है। वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी।

इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता सुनील पिल्लई ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहने के दौरान कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। जिस पर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जेल में बंद कैदी को संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार मिले हैं। उसका पालन किया जाना चाहिए।

दरअसल, 26 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया था कि प्रदेश की कई जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। कुछ जिलों में जेल निर्माण कार्य भी जारी है। वहीं 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे। वर्तमान में 33 जेलों में 2979 सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं उपलब्ध हैं। 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है। साथ ही कैदियों की सुरक्षा के लिए पांच केंद्रीय जेलों के लिए पांच नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर तथा पांच जिला जेलों के लिए पांच नए जनरेटर खरीदे जा रहे हैं। कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिए थे कि वर्तमान शपथ-पत्र में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए तथा जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जाए।

अमृत भारत स्टेशन के विकास कार्यों पर जीएम ने जताई नाराजगी

कोरबा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की लेटलतीफी और अस्पष्ट ड्राइंग डिजाइन को लेकर जीएम तरुण प्रकाश ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। तत्काल सुधार कार्य करने के निर्देश भी दिए। यात्री सुविधाओं के विस्तार की बात पर उन्होंने कहा कि कोरबा में पैसेंजर्स की संख्या काफी कम है। इसके कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू करने के लिए विचार चल रहा है। ट्रेनों की लेटलतीफी और कैंसिलेशन के सवाल पर उन्होंने फिलहाल रेल मंडल के अंतर्गत कई विकास कार्यों के प्रोसेस में होने की बात कही है।

जीएम ने स्टेशन के बाहर कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। कार्य में अस्पष्टता की बात कहते हुए वह बेहद नाराज हुए। उन्होंने कहा कि कौन सा ट्रैफिक किधर से आएगा और फिर वह कहां जाएगा, पार्किंग कहा होगी। इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। इस स्थिति को बिना स्पष्ट किए काम कराना उचित नहीं है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के जीएम तरुण प्रकाश के साथ डीआरएम राजमल खोईवाल भी कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कोरबा पहुंचे थे। कोरबा प्रवास के दौरान उन्होंने स्टेशन के अंदर और बाहर का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने चल रहे निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने कहा। यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने दोनों तरफ चल रहे काम के बीच संकरा रास्ता दिया गया है। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी। इसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। सुविधा बढ़ाने की बात पर जीएम तरुण प्रकाश ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरबा में पैसेंजर की संख्या काफी कम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार सुविधाएं जरूर बढ़ाई जाएंगी। फिर चाहे वह कोरबा से रायगढ़ तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग हो या फिर कोरबा से दूसरे राज्यों के लिए यात्री ट्रेनों के संचालन का प्रश्न हो।

जीएम तरुण प्रकाश ने यह भी कहा कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम प्राथमिकता पर है। जिसके कारण कई ट्रेनों को लेट और कैंसिल करना पड़ रहा है। आने वाले 1 साल तक यह कार्य चलते रहेंगे। इसके बाद ट्रेन काफी तेज गति से चलेंगी।

रेल संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल भी जीएम से मिला। उन्होंने पूर्व में हुई समीक्षा बैठक के निर्णय को अमल नहीं करने व पिटलाइन को पूर्ण रूप से शुरू करने की बात रखी। उनसे जीएम ने कहा कि पिटलाइन रेलवे बोर्ड का मामला है। वहां से यदि कोई दिशा निर्देश मिलेगा तो आगे काम किया जाएगा। जीएम अपने विशेष सेलून ट्रेन से कोरबा पहुंचे थे। उन्होंने कोयला लदान से जुड़ी समीक्षा की। दीपका, गेवरा कोल साइडिंग का निरीक्षण किया और फिर वापस लौट गए।

बीजापुर में नक्सलियों का एक और धमाका

आईईडी धमाके में दो जवान घायल

बीजापुर। छत्तीसगढ के बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों द्वारा प्लांट आईईडी की चपेट में आकर सुरक्षाबलों के जवान घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए बीजापुर अस्पताल लाया गया है। घायल जवानों के नाम मृदुल बर्मन और मोहम्मद इसहाक है। जिनके पैर में चोट लगी है। दोनों जवान कोबरा यूनिट से हैं और रायपुर रेफर कर दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र पुतकेल कैंप से सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त पार्टी एरिया डॉमिनेशन पर निकली हुई थी। एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी के दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट की गई। आईईडी के ब्लास्ट होने से इसकी चपेट में आकर सुरक्षाबल के दो जवान घायल हो गए।

दोनों घायल जवानों को बीजापुर अस्पताल लाया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया है कि जवानों की हालत सामान्य और खतरे से बाहर बताई गई है। बता दें कि बीते 12 जनवरी को जांगला थाना क्षेत्र के जैगुर के पास नक्सलियों द्वारा आईईडी प्लांट किया गया था। जिसकी चपेट में डीआरजी के दो जवान रामसाय मज्जि और गजेंद्र साह घायल हो गए। उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ओबीसी वर्ग महासभा के बैनर तले होगा आंदोलन

बालोद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण के बाद से ओबीसी वर्ग उपेक्षित महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ ओबीसी वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यहां पर आने वाले दिनों में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं, वह सरकार के फैसले से संतुष्ट हुए तो पूरा ओबीसी वर्ग यहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। बालोद शहर के साहू सदन में मीडिया से चर्चा के दौरान पिछड़ा वर्ग महासभा ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग महासभा के साथ गलत किया है और कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी राजनीति खत्म करने की यह साजिश है।

पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को दबोचा

दुर्ग। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने व्यवसायी के बेटे की शादी कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। प्रार्थी ने पुलिस रिपोर्ट में बताया है कि शादी के बाद दूल्हे ने कथित पत्नी का आधार कार्ड मांगा तो बहाने बनाने लगी। शक हुआ तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जिसके बाद प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कथित पत्नी समेत सातों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सभी आरोपियों ने अपने नाम बदलकर अपना परिचय बताया था। इस मामले में कथित दुल्हन पूर्वा जैन, विवाह एजेंट सरला, पूर्वा के भाई संतोष समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। सभी आरोपियों ने मिलकर प्रार्थी से अलग-अलग बहाना बनाकर 17.5 लाख रुपए की ठगी की है। इस मामले में एक आरोपी मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है।

स्थानीय लोगों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, बची जान

बलरामपुर रामानुजगंज। गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे के करीब रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक एक में स्थित पेट्रोल पंप रोड में नित्यांश ट्रेडर्स के सामने युवक बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल युवक को 100 बिस्तर अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक, नित्यांश ट्रेडर्स के सामने एक्सिस बैंक में काम करने वाले उमेश सिंह उम्र 35 वर्ष बाइक से बैंक जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। जिससे उमेश के सिर में गंभीर चोट लगी। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अजय गुप्ता एवं संतोष गुप्ता की नजर पड़ी तो तत्काल उन्होंने उमेश को सड़क के किनारे किया। वहीं साई बाबा पब्लिक स्कूल के भाई रूपेश गुप्ता अपने चार चक्का वाहन से बच्चों को लेने जा रहे थे। उन्होंने अपने वाहन को रोककर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शंभू गुप्ता के सहयोग से 100 बिस्तर अस्पताल पहुंचाया। जहां घायल का इलाज हुआ। जब इस प्रकार की घटना होती है तो लोग भीड़ जरूर लगा देते हैं।

जलप्रपात रमदहा सैलानियों का बना पसंदीदा स्थल

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित रमदहा जलप्रपात अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर ब्लॉक से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहरासी वन परिक्षेत्र में बनास नदी की गोद में बसा यह स्थल हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जलप्रपात से लगभग 100 फीट की ऊँचाई से गिरते पानी का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। चारों ओर फैले घने जंगल, हरियाली, और शांत वातावरण रमदहा जलप्रपात एक मनमोहक पिकनिक स्थल है। ठंड और बरसात के मौसम में इसकी सुंदरता अपने चरम पर होती है। तेज धारा, झरने की गूंज, और पानी की धुंध का नजारा प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जलप्रपात तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है।

जगदलपुर में खाना बनाते समय झुलसी महिला

जगदलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के महादेवघाट में रहने वाली महिला खाना बनाते समय अचानक आग से झुलस गई। इलाज के दौरान महिला मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं, कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि महिला 70 प्रतिशत से ऊपर जल गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी शिवानंद सिंह ने बताया कि महादेवघाट में रहने वाली निशा राय पत्नी अंकित राय (24) पांच जनवरी को अपने घर में अकेले थी। दोपहर को खाना बनाने के लिए किचन में गई, जहां गैस को चालू करने के बाद लाइटर का उपयोग करने पर नहीं जला। इसके बाद निशा ने जैसे ही माचिस का उपयोग किया, गैस के कारण आग लग गई और वह झुलस गई। इसके बाद आसपास के लोग महिला को पहले महारानी अस्पताल ले गए, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए पांच जनवरी की दोपहर को मेकाज में भर्ती किया गया। 10 दिनों तक चले उपचार के दौरान महिला ने 15 जनवरी को दम तोड़ दिया।

भिलाई में व्यापार महाकुंभ, मध्य भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक आयोजन

भिलाई। तीन दिवसीय व्यापार महोत्सव 16 से 19 जनवरी के आयोजन को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव व्यापार, उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यापारिक जगत को एक मंच देता है।

व्यापार महोत्सव न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत में अपने विशाल आकार और विविधता के कारण प्रसिद्ध हो रहा है। इस महोत्सव में उद्योग जगत से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

अजय भसीन ने कहा पूरे हिंदुस्तान में कुंभ की चर्चा है। इसी तर्ज पर भिलाई में व्यापारियों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। इसमें जो भी व्यापारी सेमिनार अटेंड करेगा, वह खुद को अपग्रेड करेगा। स्टार्टअप की बारिकियां, फंड की पूरी जानकारी और व्यापारियों को प्रोडक्ट को कैसे शो केस करना है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। हम आश्वस्त करते हैं कि व्यापारी अपने व्यापार को नई दिशा देंगे।

व्यापार महोत्सव में भारत के जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विवेक बिंद्रा भी शिरकत करेंगे। वे व्यापारियों और उद्यमियों को प्रेरित करेंगे और सफलता के मंत्र साझा करेंगे। इस महोत्सव में व्यापार और उद्योग से जुड़ी 150 से ज्यादा विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल लगाई जाएगी।

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, तकनीकी उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़ा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित होंगी। व्यापारियों और निवेशकों को एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। इससे व्यापारिक साझेदारियां और नए अनुबंध बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

व्यापार मेला ज्यादातर परंपरागत मेला जैसा लगता रहा है, इस बार हम परिवर्तन कर रहे हैं। हम केंद्रित वर्कशाप कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा का सेमिनार है। स्टार्टअप सम्मेलन है। बैंकिंग के अलावा किस हैंडल से फंडिंग कर सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा डिजिटल कांफ्रेंस हैं। सोशल प्लेटफार्म का उपयोग कैसे करें, इसकी बारिकियां सिखाई जाएगी। इंटरटेनमेंट के भी अलग अलग इवेंट हैं। 150 से ज्यादा स्टॉल लगाई जा रही है-गार्गी शंकर मिश्रा, अध्यक्ष, भिलाई चेम्बर

व्यापार महोत्सव में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। लोक नृत्य, संगीत और क्षेत्रीय खानपान के माध्यम से यहां के रंग रूप और स्वाद को अनुभव किया जा सकेगा। व्यापार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, नए व्यवसायिक विचारों को मंच प्रदान करना और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के व्यापारिक समुदाय को नई संभावनाओं के द्वार खोलने में मदद मिलेगी।

खनिज माफिया का खतरनाक साम्राज्य

बिना मानक के खुदाई से नर्क बनी ग्रामीणों की जिंदगी

खैरागढ़। खैरागढ़ और राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में खनिज माफिया के आतंक से ग्रामीणों की जिंदगी नरक बन चुकी है। बिना किसी मानक के अंधाधुंध खनन, अवैध ब्लास्टिंग और प्रदूषण ने इस इलाके को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

खैरागढ़ के ठेलकाडीह, दपका, बल्देवपुर, पेंड्रिकला और आसपास के इलाकों में खनिज माफियाओं का खौफनाक साम्राज्य फैला हुआ है। दो जिलो की सीमा पर स्थित होने और आधिकारिक साठ-गाँठ के चलते खदानों के संचालक पूरी तरह से बेख़ौफ़ हो चुके हैं। नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, 100 फीट की वैध सीमा को पार कर 150 से 200 फीट तक खनन किया जा रहा है। यह खनन न सिर्फ़ पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ग्रामीणों की जान-माल को भी जोखिम में डाल रहा है।

खनिज माफिया के अवैध खनन और ब्लास्टिंग ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। गहरे खड्डों और लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव के लगभग सभी मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। खेत बंजर हो गए हैं, और भूजल स्तर इस कदर गिर चुका है कि अब पानी के लिए भी मारामारी होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर रोज़ धमाकों से उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। खनिज माफिया नियमों को रौंदते हुए बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं।

धमाकों से घरों की नींव हिल रही है, दीवारें दरक रही हैं, और पूरा इलाका कांप रहा है। धमाके इस कदर तेज़ होते हैं कि ग्रामीणों की नींद उड़ जाती है। इसके लिए न तो खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमति ली जाती है, और न ही पुलिस को सूचना दी जाती है। धमाकों के बाद बड़े-बड़े पत्थर गांव में गिरते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। खनन के कारण उड़ने वाली धूल ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अस्तित्वहीन बना दिया है।

संक्षिप्त समाचार

स्पैडेक्स मिशन की सफल डॉकिंग पर सीएम ने इसरो को दी बधाई

रायपुर। भारत ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने स्श्चड्डस्त्रद्गङ्ग मिशन की सफल डॉकिंग कर स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बन गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भारत की इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम और देश वासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- 'अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धिज भारत ने स्श्चड्डस्त्रद्गङ्ग मिशन की सफल डॉकिंग कर इतिहास रचते हुए स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो की पूरी टीम और देशवासियों को हार्दिक बधाई! जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत!

आईएएस नम्रता गांधी का पीएम अवार्ड के लिए हुआ चयन, पीएम मोदी करेंगे सम्मान

रायपुर। धमतरी कलेक्टर आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी आईएएस अधिकारी है। इससे पहले दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और आईएएस सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था। जनवरी 2024 से धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने भखारा नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सिलघट तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई। गंगरेल नहर के पानी को सिलघट एनीकट के पास नगर पंचायत के इनटेक वेल के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर वाटर ट्रीटमेंट करते हुए पिछले दिनों से भखारा नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति शुरू करवाई गई। इस तरह कलेक्टर नम्रता गांधी की दूरदर्शिता से नगर पंचायत क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया। इस कार्य की वजह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग रखी है। केन्द्रीय राज्य मंत्री साहू ने शिक्षा मंत्री को पत्र में अवगत कराया कि जिले में गरीब आदिवासी और कमजोर तबकों को उन्नत शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के अधिकांश प्रतिभा शाली बच्चे नवोदय विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी नवोदय मल्हार में संचालित है। वहीं नवोदय में बहुत कम बच्चों का ही चयन हो पाता है जिसके चलते काफी बच्चे इस विद्यालय के लाभ से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने अपने पत्र में जिलाध्यक्ष जे। पी। पैकरा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ विकास खण्ड गौरेला का पत्र भी संलग्न किया है।

पीडीएस के तहत माह जनवरी के लिए 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन

रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है। जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इन्द्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए एक लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा। माह जनवरी 2025 के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 31 जनवरी तक करने को कहा गया है।

राज्यपाल ने डॉ. रवि रत्न सक्सेना को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया

रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका द्वारा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रवि रत्न सक्सेना प्रोफेसर और एसोसिएट निदेशक (अनुसंधान), अनुसंधान सेवा निदेशालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन जिला दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है।

पिछली सरकार ने किया शराब घोटाला, जेल में हैं कई लोग : शर्मा

कबीरधाम। राज्य के बहुचर्चित दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा व बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर पहुंचे कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ये घोटाला किया है। इस मामले में कई लोग जेल में है। ईडी इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद हाल में ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ईडी के पास प्रमाण है। कई लोग जेल में हैं। कवासी लखमा खुद उस विभाग के मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर आंच आना संभव है। डिप्टी सीएम ने कवासी लखमा के अनपढ़ होने वाले बयान पर कहा कि अगर उनका भाव है तो उन्हें जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि भी है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, जिनको दिखता भी नहीं, उनके साथ कई असिस्टेंट काम करते हैं। ऐसी व्यवस्था भी है। घोटाले के बाद ऐसे आप बोल दें तो मैं नहीं समझाता क्या स्थिति है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा प्रवास के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करते हुए प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में आयोजित पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ और श्री शिव पुराण में विधिवत पूजा-अर्चना की। यह महायज्ञ 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। उन्होंने यज्ञ स्थल की परिक्रमा की और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से भी मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि धार्मिक आयोजनों का महत्व केवल आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में सद्भावना और एकता का संचार भी करते हैं। जहां संत और साधु का आगमन होता है, वह क्षेत्र भी समृद्धि और शांति का केंद्र बन जाता है। उन्होंने इन आयोजनों को समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का सशक्त माध्यम बताया। कबीरधाम जिले में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन की परंपरा लंबे समय से रही है। इन आयोजनों को और भी विशेष बना दिया।

सबके लिए नियम बराबर: साय

करीब 2 हजार करोड़ के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। कवासी लखमा बुधवार 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कवासी लखमा की मेडिकल जांच के बाद उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां से लखमा को 21 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में आबकारी मंत्री रहते हुए पूर्व मंत्री को हर महीने 2 करोड़ रुपये दिए जाते थे।

शराब घोटाले में लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम साय- पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। शराब घोटाले में करीब 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। इसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी वो ईडी करेगी।

कांग्रेस के बदले की भावना से की गई कार्रवाई के आरोपों पर सीएम साय ने कहा सबके लिए नियम बराबर है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन गलत नहीं

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा जो आरक्षण लागू हुआ है ये सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है। कोर्ट जाने का सभी को अधिकार है।

सीएम ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना गलत नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन कर छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से काफी अच्छा काम किया गया। कई प्रदेशों में ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिसके बाद वहां ओबीसी का आरक्षण जीरो कर दिया गया। सीएम ने ये बातें बिलासपुर दौरे के दौरान कही। बता दें कि सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

हर महीने दो करोड़ रुपए पहुंचता था लखमा के पास!

खुलासे के बाद कवासी के करीबियों से पूछताछ की तैयारी में ईडी

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर रही है, इसके साथ अब ईडी कवासी के सीए के अलावा कई करीबियों को भी तलब करने की तैयारी में है।

सूत्रों के अनुसार, कवासी लखमा को कस्टोडियल रिमांड में लेने के बाद ईडी ने देर रात तक की छापेमारी में बैंक डिटेल जमा करने पर मिले मनी ट्रेल को लेकर लंबी पूछताछ की। इसके बाद अब ईडी कवासी के करीबियों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह समेत इकबाल खान के बयान में दो करोड़ रुपए प्रतिमाह कवासी लखमा को दिए जाने का खुलासा हुआ है। कवासी लखमा तक यह पैसे पहुंचाने वाले कन्हैयालाल कुर्रे और जगन्नाथ उर्फ जग्गू समेत जयंत देवांगन को भी बुलवाकर ईडी वन टू वन पूछताछ होगी।

ईडी वकील ने किया लेन-देन का खुलासा

बता दें कि बुधवार को ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार की जानकारी देते हुए बताया था कि कवासी लखमा को प्रति महीना दो करोड़ रुपए के हिसाब से 72 करोड़ रुपए के लेन-देन सामने आया है।

कांग्रेस भवन निर्माण में किया उपयोग

वकील ने बताया कि आबकारी अधिकारी इकबाल और जयंत देवांगन के साथ कन्हैया लाल कुर्रे पैसे ले जाकर कवासी लखमा के पास पास छोड़ते थे। साथ ही साथ जग्गू राजू के पास से कई सबूत सामने आए है। इन पैसों से दो काम में उपयोग किया गया है। सुकमा में पुत्र के घर के और कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया है।

गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसियों ने कराया सुकमा बंद

सुकमा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर जिला कांग्रेस ने एक दिवसीय सुकमा बंद का आह्वान किया है, जिसका जिला मुख्यालय में असर देखने को मिल रहा है। सुबह से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए लखमा की गिरफ्तारी पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बुधवार को श्वष्ठ (प्रवर्तन निदेशालय) ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड के लिए जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया था। जहां सुनवाई के बाद लखमा को 22 जनवरी तक के लिए 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया था। इस मामले में लखमा के बेटे हरीश को भी आरोपी बनाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।

नागरिकों के लिए 13 स्मार्ट और 4 पिंक टॉयलेट का हो रहा है नि:शुल्क संचालन

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार राजधानी शहर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में आमजनों को जीवन में निरंतर दैनिक स्वस्थ परिवेश देने मॉनिटरिंग सहित कार्य निरंतर किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 10 जोन अंतर्गत 70 वार्ड हैं, जिसमें 201 सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं। सामुदायिक शौचालय की संख्या 112, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 72, स्मार्ट टॉयलेट की संख्या 13 और पिंक टॉयलेट की संख्या 4 है। रायपुर शहर के बस्तियों में स्थित 112 सामुदायिक शौचालयों का संचालन और संधारण स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उपयोग रहवासियों के लिये नि:शुल्क किया गया है। स्मार्ट टॉयलेट और पिंक टॉयलेट भी नि:शुल्क आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। नगर पालिक निगम रायपुर में निर्मित 4 पिंक टॉयलेट हैं, जो सिर्फ महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कर संचालित किए जा रहे हैं। सर्वसुविधायुक्त 13 स्मार्ट टॉयलेट हैं, जिसका संचालन और संधारण विज्ञापन कंपनी ग्रेसफुल (इंडिया) मीडिया द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा

जीवन अनमोल है, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें

रायपुर। प्रदेश में मनाए जा रहें 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाईक चलाकर प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी के रोहणीपुरम गोल चौक पहुंचकर बाईकर्स और पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बाईक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों सहित चार पहिया वाहन चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान साय ने हरी झण्डी दिखाकर भव्य बाईक रैली को रवाना भी किया। स्वंयसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। मनुष्य जीवन में पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। उन्होंने कहा कि एक तरह से हमारा जीवन परिवार के लिए है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन चलाते समय हम सभी को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट अवश्य ही पहनना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा सीमित रफ्तार में ही वाहन चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कभी भी नशा कर वाहन चलाने से बचना चाहिए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को यातायात नियमों के अनुसार वाहन चलाने, यातायात के नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया, ताकि अपने जीवन के साथ-साथ दूसरे लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहें और पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी 2025 तक मनाया जा रहा है। इसके तहत रायपुर यातायात पुलिस द्वारा लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जरूरी नियमों और संसाधनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोचक तरीके से सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा की थीम पर बैनर-पोस्टर लगाकर उपयोगी संदेश दिए जा रहें हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे अभियान के लिए अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में वाहन चालकों, स्थानीय नागरिकां और छात्र-छात्राओं के पालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ। गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, पुलिस और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे।

मंत्री केदार ने की धान खरीदी और सहकारी समितियों के कामकाज की समीक्षा की

■ कहा- सहकारिता से समृद्धि हमारा लक्ष्य

रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सरगुजा प्रवास के दौरान वहां के सर्टिक हाउस में सहकारिता एवं सहकारी बैंकों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान धान खरीदी उठाव एवं मिलिंग, किसानों को कृषि ऋण, माईक्रो एटीएम की स्थापना आदि की गहन समीक्षा की। उन्होंने शत् प्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलबध कराने पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने के भी निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकार से समृद्धि हमारा लक्ष्य है। सहकारिता के माध्यम से किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास लगातार किया जाना चाहिए।

उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एम पैक्स दुग्ध, मत्स्य एवं लघु वनोपज सहकारी समितियों का गठन सुनिश्चित करने, सीएससी पैक्स के माध्यम से कॉमस सर्विस सेन्टर की स्थापना के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण और किसानों की विविध जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बने, इससे उनकी उपयोगिता साबित होगी और वे आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गई कि सरगुजा संभाग के पांचों जिलों में सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी की व्यवस्था और उठाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब तक 5 जिलों में लगभग एक लाख 5 हजार किसानों से 5 लाख 75 हजार टन धान खरीदा गया है। जिसमें सरगुजा जिले में 30 हजार 414 किसानों से एक लाख 69 हजार टन धान क्रय करते हुए लिकिंग में 364 करोड़ रूपए की वसूली की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ में एक लाख 21 हजार 539 किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में 451 करोड़ रूपए वितरित किए गए थे। रबी फसलों के लिए 14 जनवरी 2025 तक की स्थिति में 11 हजार 647 किसानों को 16 करोड़ 83 लाख रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है।

बैठक में जानकारी दी गई कि पांचों जिलों की 153 समितियों द्वारा माइक्रो ए।टी।एम के माध्यम से 6 करोड़ 29 लाख रूपए का त्वरित भुगतान धान बेचने वाले किसानों को नियमानुसार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 09 समितियों द्वारा कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया गया है, जिसमें 691 सदस्यों की अंशपूंजी 4।41 लाख रूपए है। अम्बिकापुर सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधीन 40 नवीन समितियों का गठन किया गया है।

124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के 23 लाख किसानों ने धान बेच चुके हैं। अभी तक बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए किसानों को भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सीजीपीएससी घोटाला : टामन सोनवानी के भतीजे और गोयल के बेटे-बहू पर गंभीर आरोप

सीबीआई ने विशेष कोर्ट में पेश किया दो हजार पन्नों का चालान

रायपुर। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने गुरुवार को चालान पेश किया। सीबीआई की विशेष कोर्ट में पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन कथित मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के विरुद्ध दो हजार पन्नों का चालान पेश किया गया, जिसमें घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और आरोप शामिल हैं।

चालान में सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है।

इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। परीक्षा में हेरफेर करने के लिए बड़ी धनराशि का लेन-देन किया गया था। सीबीआई की ओर से पेश किए गए चालान में मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग (छ.ग.)

संक्षिप्त मैन्युअल जोनल निविदा सूचना कमांक-23
Email id: ee-res.durg@gov.in

ज्ञा.कं. 70 / व.ले.लि. / ग्रा.यां.से./2024-25 — दुर्ग, दिनांक 14/01/2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग दुर्ग अंतर्गत विभिन्न मदों में वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत रूपये 10.00 लाख तक लागत के छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का सम्पादन करना। (जोनल निविदा ग्रुप क्र. 14, 15,16, 17 एवं 18)	20.00 लाख प्रति ग्रुप

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://res.cg.gov.in में दिनांक 14.01.2025 से देखी जा सकती है एवं ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 28.01.2025 तक है।

जी-242505353/2

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग (छ.ग.)

अब उपयोगिता खोने लगे हैं सियासी गठबंधन

राजेश बादल

भारतीय राजनीति में दलों के बीच गठबंधन अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। करीब आधी सदी पहले इन गठबंधनों की शुरुआत हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता इसके पीछे थी। उसके बाद लंबे समय तक राष्ट्रीय हित में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तमाम पार्टियां एक मंच पर उपस्थित रहीं और अपने तीव्र आवेग का प्रदर्शन करती रहीं। एक जमाने में इन पार्टियों को वैचारिक आधार पर साथ काम करते देखना सुखद था। लेकिन बाद के वर्षों में सिद्धांत और विचार सियासत से गायब होते गए। गठबंधनों में शामिल छोटे-बड़े दलों की प्राथमिकताएं गड्डमड्ड होती रहीं। उससे जम्हूरियत की भावना कमजोर पड़ी और व्यक्तिगत स्वार्थ तथा नवसामंत पनपते रहे। इसका एक कारण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे राजनेताओं की उपस्थिति थी, जो आजादी के बाद उभरे थे। उनके लिए आदर्श और सिद्धांत सर्वोपरि थे। वे राजनीति में नैतिक मूल्यों के हामी थे। खेद है कि उनके जाने के बाद ऐसे राजनेताओं का विलुप्त होना शुरू हो गया। सियासत का रंग बदल गया। देशहित हाशिए पर चला गया। राजनीति कारोबार में तब्दील होती गई। मुल्क का जहाज छोटे-छोटे अनेक उपकप्तानों के सहारे बढ़ता गया। एनडीए और यूपीए दो दशक पहले तक अपने सर्वोत्तम स्वरूप और आकार में थे। गठबंधन -राजनीति का एक तरह से वह स्वर्ण युग कहा जा सकता है। दरअसल किसी भी धड़कते हुए लोकतंत्र में मतभेद अत्यंत स्वाभाविक हैं। वे गठबंधनों में भी समय-समय पर दिखाई देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले एनडीए तथा कांग्रेस के नेतृत्व में बने यूपीए के भीतर कई बार यह मतभेद सामने आए और आपसी तालमेल से सुलझाए जाते रहे। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनी, जब छोटे दलों के अंदर असुरक्षा बोध पनपा। उन्हें लगा कि बड़ी पार्टी उन्हें गठबंधन में साथ लेकर चल तो रही है, मगर साथ रहने के खतरे भी हैं। उनकी इस सोच का आधार भी था। बड़े दल जब चुनाव मैदान में सामने आते तो छोटे दलों का वोट बैंक बड़ी पार्टियों के साथ तो चला जाता पर बड़ी पार्टियों के मतदाता छोटी पार्टियों को वोट देने से छिटकते रहे। कई चुनाव परिणाम इसका गवाह हैं। इससे छोटे दल और नाटे-बौने होते गए, जबकि बड़ी पार्टियां अपनी काया का विस्तार करती रहीं। लोकतंत्र का बगीचा इस भावना से नहीं चलता। भारतीय लोकतंत्र की इस बगिया में सभी किस्म के फूलों के लिए भरपूर संभावना है। वे अपनी हर तरह की विशिष्ट वैचारिक खुशबू बिखेरते हुए खिल सकते हैं। गेंदे से लेकर गुलाब तक सब भारतीय गुलशन को महका सकते हैं। ऐसे में कोई यह फूल दावा नहीं कर सकता कि वह बगीचे का राजा फूल है। पर, हुआ इसके उलट। पार्टियों में यह संक्रामक राजा बोध हमें नजर आया। छोटे दलों में इसी तर्ज पर अपनी सुरक्षा में अधिनायकवाद विकसित हुआ। मौजूदा राजनीति किसी भी क्षेत्रीय दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं दिखाती। वहां एक शिखर पुरुष या शिखर महिला है, जो पार्टी की गाड़ी को अपने अंदाज में खींच रहा है। इन दलों में संगठन चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। अरसे से इन दलों में एक ही चेहरा सुप्रीम है। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि भारत जैसे विराट देश के नागरिक आजादी के सतहत्तर बरस बाद भी राजा-रानी युग की मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं और वे अभी भी एक सुल्तान अथवा महाराजा के अधीन रहना पसंद करते हैं? देखा जाए तो छोटी पार्टियों का आकार और असुरक्षा बोध उनके ढांचे में लोकतंत्र की अनुपस्थिति का कारण भी है। गठबंधन का बड़ा दल उनको आंखें दिखाता है तो उन्हें अपने अस्तित्व पर हमला लगता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब बिहार में यह बयान दिया था कि अब भारतीय राजनीति में छोटे दलों का भविष्य नहीं रहा और आने वाले दिनों में वे समाप्त हो जाएंगे तो उसका संभवतया मतलब यही था। हम देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव मंझोले दल सिकुड़ते जा रहे हैं। बेशक बंगाल या तमिलनाडु अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन तो उनके लिए भी चेतावनी भरा संदेश दे रहे हैं। एक अनुभव यह भी है कि गठबंधन में प्रतिपक्ष तनिक ज्यादा चुनौतियों का सामना करता है। सत्ताधारी गठबंधन के सामने कम मुश्किलें पेश आती हैं। कारण यह कि सरकार के साथ रहने पर छोटे दल सुख-सुविधाओं का भरपूर लाभ लेते हैं। उनके काम होते रहते हैं और कार्यकर्ताओं का रौब बना रहता है। दूसरी ओर प्रतिपक्षी गठबंधन को अपने दलों या उनके विधायकों तथा सांसदों के शिकार का खतरा रहता है। यह बीमारी हालिया दौर में ज्यादा दिखाई दी है।

भाजपा मुख्यालय के करीब कांग्रेस मुख्यालय

समीरात्मज मिश्र

24 अकबर रोड, नई दिल्ली-11. यह पता है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन 15 जनवरी से यह पता बदल जाएगा और कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय होगा 9ए कोटला रोड, नई दिल्ली। पार्टी ने मुख्यालय के छह मंजिला इस नए भवन का नाम रखा है इंदिरा गांधी भवन।

कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 15 जनवरी को इस नई इमारत का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने बताया, 15 जनवरी, 2025 को सुबह 10 बजे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी नए एआईसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन किया। इस इमारत का निर्माण तभी शुरू हुआ था जब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थीं। 9ए कोटला मार्ग पर इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

वेणुगोपाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह में कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य, कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारी, एआईसीसी पदाधिकारी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख, सीएलपी नेता, सांसद, वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित करीब चार सौ वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस नये परिसर में कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठन, जैसे- महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के भी दफ्तर स्थानांतरित किए जाएंगे। अब 26 अकबर रोड पर बने कांग्रेस सेवा दल के दफ्तर और 5 रायसीना रोड पर बने एनएसयूआई के दफ्तर को भी इसी नए इंदिरा भवन में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा।

कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर की इस इमारत का शिलान्यास साल 2009 में तब हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। लेकिन इसके निर्माण में 15 साल क्यों लग गए, यह भी बड़ा सवाल है। इस देरी की मुख्य वजह संसाधनों की कमी को बताया जा रहा है, ये अलग बात है कि 2009-2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी और तमाम राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं।

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की इस नई इमारत का पता 9ए कोटला मार्ग जरूर है लेकिन इसे जमीन का आवंटन उसी दीनदयाल मार्ग पर हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, लेकिन पार्टी ने अपने मुख्य प्रवेश द्वार को कोटला मार्ग पर बनाया है ताकि दफ्तर का पता यही रहे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय साल 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनी नई इमारत में शिफ्ट हुआ था जो कि एक आलीशान और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। बीजेपी का मुख्य द्वार दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर खुलेगा, जिसका पता 6, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग है जबकि कांग्रेस ने तय किया है कि उसका मुख्य द्वार कोटला रोड पर होगा और उसका पता होगा 9ए, कोटला रोड।

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं और कांग्रेस के इतिहास पर लिखते रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही अपने मुख्यालय का दफ्तर चाहते थे क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भी यहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्यालय यहां पहले बन गया और आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के दफ्तर भी इसी रोड पर हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कोटला रोड को अपना नया पता बनाया है।

मीडिया से बातचीत में अरविंद कुमार सिंह कहते हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर पहले से यहां था इसलिए पार्टी के लोग मुख्यालय भी यहां बनाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री थे, तब इस रोड पर आरएसएस के संगठनों को 22 दफ्तर आवंटित कर दिए गए थे। एक तरह से उस जगह को बीजेपी ने तभी से आरक्षित कर लिया था। फिर जब साल 2009 में पार्टियों के लिए जगह का आवंटन हुआ तो बीजेपी को भी वहीं जमीन मिल गई दफ्तर बनाने के लिए। हालांकि नेहरू के समय जब कांग्रेस पार्टी के लिए नई दिल्ली में दफ्तर की जगह तलाश की जा रही थी तब इसी जगह को प्राथमिकता दी गई थी। इसका बड़ा कारण यह था कि यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक है और उस समय दूर-दराज से आने वाले ज्यादातर लोग ट्रेन से ही आते-जाते थे।

24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर 1978 में उस वक्त शिफ्ट हुआ था जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी हार गई तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टूट गई। उन्हीं परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने जनवरी 1978 में पार्टी के दफ्तर को यहां शिफ्ट किया। ये दिल्ली के लुटियंस इलाके का टाइप 7 बंगला था, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद जी वेंकटस्वामी के नाम पर आवंटित था। 24 अकबर रोड का यह बंगला उससे पहले भी काफी अहम जगह हुआ करती थी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर होने के अलावा यहां इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी हुआ करता था और उससे भी पहले इसे बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। इस घर का यह नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था क्योंकि इसी बंगले में म्यांमार की भारत में राजदूत डॉक्टर खिन काई अपनी बेटी आंग सान सू ची के साथ रहने आई थीं।

लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के लिए इस बंगले का चुनाव करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इसी से जुड़ा हुआ 10 जनपथ का भी बंगला है जो उस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था। यही 10 जनपथ बाद में सोनिया गांधी का आवास बना और अभी भी यह उनका आवास है।

24 अकबर रोड को कांग्रेस का मुख्यालय भले ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया था लेकिन यह इमारत कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के लिए काफी भाग्यशाली साबित हुई क्योंकि 1980 के चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सत्ता में फिर वापसी हुई। यह दफ्तर देश के चार प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के अलावा सात पार्टी अध्यक्षों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हाराव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यकाल का गवाह रह चुका है।

वैसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर जंतर-मंतर रोड पर था। अरविंद कुमार सिंह बाते हैं, आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर जब इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया तो यह नया मुख्यालय 7 जंतर-मंतर रोड था। यह भवन साल 1969 तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा। लेकिन 1969 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और फिर दफ्तर भी यहां से चला गया। हुआ यह कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने के मुद्दे पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच जबर्दस्त विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी ही दो हिस्सों में टूट गई। पुराने नेताओं की पार्टी हुई कांग्रेस (ओ), जिसका मुख्यालय 7 जंतर-मंतर ही रहा जबकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम रखा कांग्रेस (आर)। अब इंदिरा गांधी को एक नए दफ्तर की जरूरत थी। तो कांग्रेस के पुराने नेता और नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रहे एमवी कृष्णप्पा के घर विंडसर प्लेस को इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया।

साल 1971 में पार्टी का दफ्तर 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हो गया और लेकिन साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी में एक बार और टूट हुई तो इंदिरा गांधी ने जनवरी 1978 में पार्टी मुख्यालय को 24 अकबर रोड पर शिफ्ट कर दिया और तब से लेकर यह अब तक पार्टी का मुख्यालय है।

हालांकि कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू का घर ही था जो स्वराज भवन के रूप में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा। मोतीलाल नेहरू जाने-माने वाकील और कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने इलाहाबाद के चर्चलेन में एक बड़ा बंगला बनवाया जिसका नाम आनंद भवन रखा। कांग्रेस के नेताओं का उस घर में आना-जाना रहा और एक तरह से वह राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का एक केंद्र बन गया। साल 1930 में मोतीलाल नेहरू ने उसके पास में ही एक और घर बनवाया। अब पुराने घर का नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया गया और जो नया घर बना उसे आनंद भवन का नाम दिया गया। स्वराज भवन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होने लगा और आनंद भवन में नेहरू परिवार रहने लगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

वास्तव में महाभारत और श्रीमद्भागवत की कविता में जो अन्तर प्रतीत होता है, वह उक्त दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप ही है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ है, उसमें स्वाभाविकता का साम्राज्य होना ही चाहिये था। इतिहास में तत्तद् व्यक्तियों का चरित्र वर्णन करने के बजाय अनावश्यक अलङ्कारों और छन्दों का समावेश करना चरित्र-चित्रण की मौलिकता का विनाश करना है! विभिन्न: प्रकृति रखने वाले पात्रों के स्वभाव पर परदा डालना है!! एवं पाठकों को इतिकर्तव्यता के निर्णय का अवकाश न देकर अपनी वाक्चातुरी से पथभ्रष्ट करना है!!! अत: वेदव्यास जी जैसे सिद्धहस्त लेखक की लेखनी से इस प्रकार की भूल कब हो सकती थी।

परन्तु श्रीमद्भागवत भक्तिप्रधान ग्रन्थ है इसमें रस की मुख्यता है । पाठकों के शुष्क हृदयों को वात्सल्य रस के महामहिम समुद्र की छलकती, उत्ताल तरंगों से आप्लावित करने की आवश्यकता थी। अनेक अलङ्कारों और सुस्वर छन्दों के स्वर्ण सुयोग से सहृदयहृदयों को पाठमात्र से तन्मयतापूर्वक श्रात्म-विस्मृति के आनन्द-पयोनिधि में निमग्न करने की जरूरत थी अत: वेदव्यास जी ने विषय के अनुरूप ही उक्त पुराण में प्राञ्जल शैली को स्थान दिया। इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद कौन ऐसा समझदार होगा जो कि महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण के प्रतिपाद्य विषयों को गजनिमीलिका से भुलाकर भाषाविज्ञान की कल्पना के आधार पर इन्हें भिन्न-कविनिर्मित कहने का साहस करेगा!

इस तरह इस अध्याय में- सत्यार्थप्रकाश कुलयात आर्य मुसाफिर, पुराण तत्व प्रकाश, पुराणमत पर्यालोचन तथा अन्यान्य ट्रैक्टों में किये गये प्रतिवादियों के समस्त आक्षेपों का समाधान आ गया है।

क्रमशः ...

ययाति स्वर्ग से गिरकर पुनः पहुंचे स्वर्ग

आशुतोष गर्ग

यह उस समय की बात है, जब राजा ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटाकर अपना बुढ़ापा उससे ले लिया था। इसके बाद पुरु को राजपाट सौंपकर ययाति तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसी तपस्या के बल पर उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला और वह देवराज इंद्र के साथ आनंद से वहां रहने लगे। एक दिन इंद्र ने ययाति से पूछा, 'नहुषनंदन! आपने गृहस्थाश्रम-धर्म का पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे पूछता हूं कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं?' इसके उत्तर में ययाति ने कहा, 'देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता।'

ययाति का दंभपूर्ण दावा सुनकर इंद्र बोले, 'राजन, आपने बड़े, छोटे लोगों और अपने समान सभी लोगों का तिरस्कार किया है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने के कारण आपका पुण्य क्षीण हो गया है। इसलिए अब आप स्वर्ग में नहीं रह सकते। आपको पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा।' ययाति ने कहा, 'ठीक है। यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया, तो मैं धरती पर संतों के बीच में ही गिरूं।' इंद्र ने ययाति की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा ययाति देवलोक से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे, जहां अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवि नाम के तपस्वी तप करते थे।

ययाति को गिरते देखकर अष्टक ने कहा, 'आपका रूप इंद्र के समान है। आपको गिरते देखकर हम चकित हैं। आप जहां तक आ गए?हैं, वहीं ठहर जाइए। हम सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। अपनी व्यथा हमें सुनाओ।' ययाति ने कहा, 'मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हुआ हूं। मुझमें अभिमान था और अभिमान नरक का मूल कारण है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। दुख और सुख दोनों में समान रहना उचित है। मैं विधाता के विधान के विपरीत नहीं जा सकता,?इसलिए संतुष्ट हूं।'

बातचीत के उपरांत ययाति ने कहा, 'देवता शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मैं अब नीचे गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है'।

अष्टक ने कहा, 'मुझे अपने पुण्य कर्मों से जो भी लोक प्राप्त होने वाले हैं, वे सब मैं आपको देता हूं, आप गिरें नहीं।' परंतु ययाति ने अष्टक के पुण्य लेने से मना कर दिया और कहा, 'मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए दान नहीं ले सकता।' फिर प्रतर्दन ने कहा, 'मुझे जिन-जिन लोकों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूं। आप यहां न गिरें, स्वर्ग में जाएं।' लेकिन ययाति ने कहा, 'मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होकर दान लेना अधर्म है।' फिर वसुमान बोले, 'राजन! मैं अपने सभी लोक आपको देता हूं। आपको यदि दान लेने में संकोच होता है, तो आप एक तिनके के बदले में इन्हें खरीद लीजिए।' परंतु ययाति बोले, 'यह क्रय-विक्रय मिथ्या है। मैंने ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया। इसलिए मैं यह काम नहीं करूंगा।'

ट्रंप का नया कार्यकाल और बदलती दुनिया

टी एन नाइनन

डॉनल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और दुनिया बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। दूसरे विश्व युद्ध से ही सबसे शक्तिशाली देश भी राष्ट्रीय संप्रभुता को सीमित करने के इच्छुक थे। वे वैश्विक नियमों और सहकारी कदमों के पालन के लिए सहमत थे। ऐसे नियम कई मामलों में बनाए गए थे, जिनमें व्यापार और शुल्क ही नहीं बल्कि परमाणु हथियार, समुद्री कानून और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा तक शामिल थी।

इसमें दो कारणों से बदलाव आया है। पहला, चीन का उदय और वैश्विक शक्ति में बदलाव। चीन यथास्थिति वाली शक्ति नहीं है, इसलिए वह उथलपुथल मचाना और अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। दूसरा है महाशक्तियों में कद्दावर नेताओं का शासन जैसे रूस में व्लादीमिर पुतिन, चीन में शी चिनफिंग और अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप।

इन दोनों घटनाओं ने क्षेत्र में जीत के लिए महाशक्तियों के बीच जंग जैसी स्थिति फिर ला दी। इराक में अमेरिका की जंग ने आहट दी थी कि आगे क्या होने वाला है। तीन वर्ष पहले पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। शी ताइवान पर हमले की तैयारी करते दिख रहे हैं। ट्रंप पनामा नहर तथा ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग की धमकी दे रहे हैं।

इसके साथ और बदलाव भी हुए हैं। बहुपक्षीयता की जगह इकतरफा कार्रवाई पसंद की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका तथा उपयोगिता में कमी आई है। जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी कदमों के मामले में भी दुनिया पिछड़ी है। भूराजनीति का मतलब हमेशा ताकत ही रहा था मगर अब यह ताकत नियम-कायदों से परे जा रही है। दक्षिण चीन सागर में भी यही दिख रहा है, गाजा में नरसंहार हो रहा है,

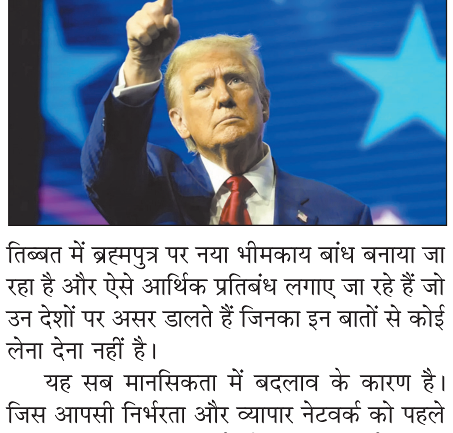

तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर नया भीमकाय बांध बनाया जा रहा है और ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जो उन देशों पर असर डालते हैं जिनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है।

यह सब मानसिकता में बदलाव के कारण है। जिस आपसी निर्भरता और व्यापार नेटवर्क को पहले लाभप्रद माना जाता था, उसे ही अब नुकसानदेह माना जा रहा है। इसलिए अब आधी सदी से चले आ रहे व्यापार उदारीकरण से दूरी दिख रही है। ऐसे में वैश्वीकरण का स्थान 'मेरा देश प्रथम' की धारणा ले रही है। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह आत्म निर्भरता की बात हो रही है। कारगर बाजार की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र हो रहा है। यह तरीका सौ साल पहले अपनाया गया था मगर कारगर नहीं रहा था। इतिहास के सबक शायद अहम नहीं रह गए।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अतीत में सबसे अधिक नियम बनाने वाला देश अमेरिका अब सबसे अविश्वसनीय देश बन चुका है। फाइनैंशियल टाइम्स के एक स्तंभकार ने पिछले दिनों सवाल उठाया कि अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा तो नहीं बन गया है। कोई नहीं जानता है कि वह आगे क्या करेगा। ये बातें दुनिया को और अधिक उथल पुथल वाली बनाती हैं, जहां पहले से बहुत अधिक अनिश्चितताएं और जोखिम हैं।

नियम और समझौते पहले से मौजूद शक्ति व्यवस्था दर्शाते हैं और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जो सहकारी एजेंडे बनाए गए थे वे पश्चिमी व्यवस्था के दबदबे के कारण संभव हुए थे। उन्हें युद्ध के बाद उभरे दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने सामने रखा था। अब वह विश्व व्यवस्था ध्वस्त हो रही है तो हमें बुनियाद की ओर लौटना होगा। चीन के उभार ने पश्चिम के सामने अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। पश्चिम मानता है कि चीन ने स्वीकार्य कारोबारी नियमों का पालन नहीं किया है और उसने व्यवस्थित ढंग से पश्चिम का औद्योगीकरण समाप्त करने काम किया है। उसने पश्चिम की तकनीक भी चुराई हैं। यही वजह है कि पश्चिम ने प्रतिबंध, शुल्क, तकनीक न देने जैसे कदम उठाए हैं। शायद ये कदम उठाने में बहुत देर कर दी गई। उद्योग में चीन के दबदबे को चुनौती नहीं दी जा सकती। गत वर्ष उसने अमेरिका के मुकालबे 12.6 गुना इस्पात, 22 गुना सीमेंट और तीन गुना कारें तैयार कीं। उसकी इलेक्ट्रिक कारें अब जापान और जर्मनी की कार बाजारों में छाने जा रही हैं। 2030 तक चीन का विनिर्माण क्षेत्र समूचे पश्चिम के विनिर्माण क्षेत्र से अधिक हो जाने का अनुमान है। नए उद्योगों के मामले में यह पहले ही दूसरों से मीलों आगे है। इस ताकत का फायदा तभी है, जब चीन वैश्विक बाजारों में रहे। लेकिन हकीकत में बाजारों को चीन की पहुंच से दूर किया जा रहा है। फिर भी 2024 में चीन 1 लाख करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष के करीब पहुंच गया। कई क्षेत्रों में यह पश्चिम से भी आगे है। यकीनन चीन की अर्थव्यवस्था में गंभीर ढांचागत दिक्कतें हैं, जिनसे उसका लगातार उभार नहीं हो पाता। परंतु यह तर्क भी दिया जा सकता है कि वह दिक्कतों से उसी कामयाबी के साथ निपट रहा है, जितना यूके, जर्मनी अथवा अमेरिका जैसे पश्चिमी देश।

हकीकत यह है कि पश्चिम को जितना ज्यादा खतरा लगा उतनी ही तेजी से उसने वे नियम त्याग दिए, जिन पर कभी वह खुद चलता था। नई दुनिया में हर देश अपने लिए लड़ रहा है और जिसमें दम है वही सही है। वास्तव में हर देश का रक्षा बजट बढ़ रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कि इससे बड़ा संघर्ष न छिड़ जाए। इससे बच गए तो भी पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी। किंतु क्या नई दुनिया नए नियमों पर सहमत होगी?

मौजूदा हालात में महाशक्तियां आक्रामकता के जरिये अपनी हैसियत भांपकर बातचीत को तैयार हों उससे पहले वैश्विक शक्ति का पाला बदल जाना चाहिए। तभी जीने का नया तरीका सामने आएगा। मान सकते हैं कि चीन अमेरिका को वापस पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में धकेल देगा मगर पूरी तरह नहीं। रूस भी जो चाहता है वह हासिल कर लेगा यानी दूर-दूर तक अपना दबदबा। यह स्थायी व्यवस्था होगी या नहीं यह कुछ अहम सवालों के जवाब पर निर्भर करता है- आज के शासकों की जगह कौन लेगा, क्या बड़ी शक्तियां जियो और जीने दो पर सहमत होंगी और मझोली शक्तियों की क्या भूमिका होगी?

आज की वैश्विक संस्थाओं में सुरक्षा परिषद की ही तरह सुधार होना चाहिए। आदर्श स्थिति में सुरक्षा परिषद को वीटो की व्यवस्था समाप्त करके यूरोपीय संघ तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की तरह भार पर आधारित मतदान की व्यवस्था अपनानी चाहिए। इससे वीटो अधिकार वाले देश अंतरराष्ट्रीय मत का ज्यादा ध्यान रखेंगे और वैश्विक शक्ति का नया यथार्थ दिखेगा। व्यापार में पूर्ण वैश्विक व्यापारिक नियमों के बजाय बहुपक्षीय व्यवस्था के आसार दिखते हैं। दुनिया के ज्यादातर गरीब अफ्रीकी देशों में रहते हैं और उन देशों की मदद के लिए नया वैश्विक समझौता जरूरी है। ये कदम आसान नहीं होंगे और न ही इनके परिणाम निश्चित हैं, शायद बीच की शक्तियां कतर से सीखकर मध्यस्थता कर सकती हैं।

आज का इतिहास

1798 समाजशास्त्र के प्रमुख फ्रांसीसी विचारक अगस्त कान्त का जन्म हुआ था।

1806 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के पोते जेम्स मैडिसन रैंडोल्फ व्हाइट हाउस में पैदा होने वाले पहले बच्चे बने।

1841 ब्रिटेन के पर्वतारोही जार्ज एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी का पता लगाया। इस चोटी का नाम भी इसके बाद एवरेस्ट रख दिया गया।

1885 सूडान में महदीसत युद्ध: अबु क्लि की लड़ाई में ब्रिटिश सेना की जीत हुई।

1893 लॉरिन ए. थर्स्टन की अगुवाई वाली नागरिक सुरक्षा समिति ने क्वीन लिली की सरकार को उखाड़ फेंका।

1912 रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की बदकिस्मत टेरा नोवा अभियान दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि रोनाल्ड अमुंडसेन की टीम ने उन्हें 33 दिनों तक पीटा था।

1913 रेमंड प्वाइनकेयर फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गये।

1917 अमेरिका ने 2.5 करोड़ डॉलर में वर्जिन आईलैंड्स को डेनमार्क से खरीदा।

1946 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के अंग ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव का आरोप लगाया, लंदन में चर्च हाउस में अपनी पहली बैठक आयोजित की।

1946 दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई।

1955 परमाणु शक्ति से चलने वाली पहली पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस ने ह्लश्ठ्ठ परमाणु ऊर्जा के तहत चल रहा है 'संदेश के साथ ग्रोनटन, कनेक्टिकट से पहली बार समुद्र में डाल दिया।

1961 बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के समर्थन और जटिलता का सुझाव देने वाली परिस्थितियों में कांगो के पूर्व प्रधानमंत्री पैट्रीस लुंबा की हत्या कर दी गई थी।

1966 अमेरिकी वायु सेना के बी -52 स्ट्रैटोफोर्सेट ने केसी-135 स्ट्रेटोटेन्कर के साथ भूमध्य सागर के ऊपर हवाई ईंधन भरने के दौरान टक्कर मार दी, जिससे स्पेन के पालोमारेस के पास जमीन पर तीन हाइड्रोजन बम गिर गए और एक चौथा समुद्र में जा गिरा।

1980 नासा ने फ्लाट्सट्कोम-3 लांच किया।

परंपरागत एवं आधुनिक चिकित्सा में समन्वय की जरूरत

ललित गर्ग

एक और नये चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के संक्रमण के उपचार को लेकर दुनिया भारत की प्राचीन प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धति की ओर आशाभरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि मानव इतिहास की सबसे बड़ी एवं भयावह महामारी कोरोना के निदान में भी उसकी भूमिका प्रभावी एवं कारगर रही है। निस्संदेह, आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने शोध-अनुसंधान व बड़े पूंजी निवेश के चलते अप्रत्याशित स्वास्थ्य उन्नति एवं चिकित्सा क्रांति की है। बावजूद इसके आधुनिक समय में भी प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां असाध्य बीमारियों के लिये कारगर बनी हुई है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की स्वीकार्यता बढ़ी है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 में जो आयुष बाजार 2.8 अरब डॉलर था, उसका आकार बीते साल तक 43.4 अरब डॉलर हो गया है। इतना ही नहीं प्राकृतिक चिकित्सा उत्पादों का निर्यात भी दुगना हुआ है। जिससे इस पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का पता चलता है। यानी इन्हें एक पूरक चिकित्सा के रूप में मान्यता मिल रही है। इन स्थितियों को देखते हुए यदि आधुनिक विज्ञान व परंपरागत चिकित्सा पद्धति में समन्वय बने तो मानवता कल्याण का नया रास्ता उद्घाटित होगा।

प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है, जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्त्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्त्वपूर्ण शक्तियों या प्राकृतिक तत्त्वों के अनुरूप एक जीवन-शैली है। यह जीवन कला तथा विज्ञान में एक सम्पूर्ण क्रांति है। इसमें प्राकृतिक भोजन, विशेषकर ताजे फल तथा कच्ची व हलकी पकी सब्जियाँ विभिन्न बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। योग, ध्यान एवं संतुलित जीवनशैली इस चिकित्सा के आधार है। प्राकृतिक चिकित्सा निर्धन व्यक्तियों एवं गरीब देशों के लिये विशेष रूप से वरदान है। इसीलिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत का जो प्राचीन सेहत का ज्ञान सदियों से हाशिये पर रहा है, उसे पिछले एक दशक में देश-विदेश में व्यापक रूप से प्रतिष्ठापित किया गया है और भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग को दुनिया में फैलाया गया है। भारत में भीषण गरीबी के चलते प्रकृति के सान्निध्य में सेहत के गुर को महसूस करते हुए महात्मा गांधी ने प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को देश में प्रतिष्ठा दी थी। आज भी उनके अनुयायी पूरे देश में इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जरूरी है कि सदियों के अनुभव से हासिल गुणवत्ता व प्रमाणिकता के परंपरागत ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मध्य तालमेल की कोशिश की जाए।

पारम्परिक एवं पूरक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन- डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रिपोर्ट (2019) के अनुसार, दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही पारम्परिक चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में, एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाएँ, स्वदेशी पारम्परिक चिकित्सा, होम्योपैथी, पारम्परिक चीनी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, आयुर्वेद व यूनानी उपचार शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ के 170 सदस्य देशों ने अपनी आबादी द्वारा पारम्परिक चिकित्सा के उपयोग पर रिपोर्ट दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भी, पारम्परिक उपचार प्रणालियों के अध्ययन और अभ्यास में क्रान्ति ला रही

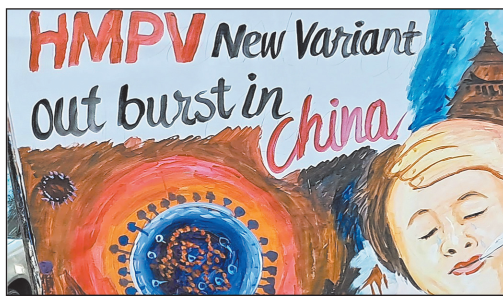

है। आयुष शब्द आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। इसी आधार पर प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक समय में प्रासंगिक बनाने के लिये भारत सरकार में आयुष मंत्रालय बना है। इसी मंत्रालय के प्रयासों से जहां आयुष बाजार को विस्तार मिला, वहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपचार में मदद मिली है। इससे रोजगार व उद्यमिता को भी नई ऊंचाइयां मिली हैं। एक ओर जहां आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन से रोजगार बढ़े हैं, वहीं इसमें प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों, फल और इससे जुड़े जैविक उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी संबल मिला है। कमोबेश इसी तरह योग से जुड़ी सामग्री का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग, आयुर्वेद, भारतीय खानपान एवं जीवनशैली को वैश्विक मान्यता मिली है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार की सहभागिता में गत वर्ष भारत के गुजरात प्रदेश के गांधीनगर शहर में प्रथम पारम्परिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और वैश्विक स्वास्थ्य एवं टिकाऊ विकास में प्रगति को आगे बढ़ाने में, पारम्परिक, पूरक व एकीकृत चिकित्सा की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए इसे व्यापक बनाने की अनेक योजनाओं पर सहमति जताई। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने आधुनिक विज्ञान एवं टैक्नॉलॉजी के ज़रिये, पारम्परिक औषधि में निहित सम्भावनाओं को साकार करने के इरादे से एक वैश्विक केंद्र स्थापित किये जाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किये और गुजरात राज्य के जामनगर शहर में बनाए जाने वाले इस केंद्र की मदद से आमजन की सेहत में बेहतरी लाने और विश्व के हर क्षेत्र में सम्पर्क व लाभ सुनिश्चित किये जाने की योजना को आकार दिया जाने लगा है।

नये विश्व की विडम्बना है कि तीव्र विकास की छाया में गरीबी का भी विस्तार हुआ है। महंगी होती आधुनिक चिकित्सा पद्धति गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। सरकारी चिकित्सा तंत्र मरीजों के भारी बोझ से चरमरा रहा है। ऐसे में यदि जीवन शैली में सुधार, सजगता व शारीरिक सक्रियता से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे पूरक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया ही जाना चाहिए। यह सुखद है कि हम देर से ही सही, इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारे आयुर्वेद के उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस दिशा में आधुनिक चिकित्सा के साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ने के लिये साझे प्रयास जरूरी हैं। पारम्परिक चिकित्सा उत्पादों और पद्धतियों के शोध का यह उपयुक्त समय है। दुनियाभर में लोग वैकल्पिक निदानों का रुख़ कर रहे हैं। इससे अधिक शोध व अधिक साक्ष्य सामने आ रहे हैं और शोध के परिणाम बेहद आशाजनक दिख रहे हैं। प्राचीन संस्कृतियों द्वारा चिकित्सा हेतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अलावा, आधुनिक रोगों से निपटने के लिए पारम्परिक समुदाय-आधारित स्वास्थ्य प्रथाओं का भी अभूतपूर्व महत्व है। चेचक के टीके का विकास इसका एक सशक्त उदाहरण है।

भारत की प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां के प्रति बढ़ते आकर्षण एवं रूझान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि हम आयुष उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उनको हम विज्ञान की कसौटी पर भी कसे। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वैश्विक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समाधान करने में सक्षम एवं कारगर बन रही है तो हमें इस पर व्यापक शोध, अनुसंधान एवं प्रयोग को बल देना चाहिए। दरअसल, भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों मसलन आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध आदि पद्धतियों की धारणा रही है कि किसी रोग को दबाने के बजाय उसके कारकों का उपचार किया जाए। पारम्परिक चिकित्सा को पूर्व-वैज्ञानिक युग की पद्धति के रूप में देखा जाता है, जिसका स्थान आधुनिक, बेहतर, विज्ञान-आधारित चिकित्सा ने लिया। हालाँकि, आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा का प्रादुर्भाव, पारम्परिक उत्पादों व प्रथाओं से ही हुआ है, जिसका एक लम्बा इतिहास है। आज लगभग 40 प्रतिशत फ़ार्मास्युटिकल उत्पाद, प्रकृति और पारम्परिक ज्ञान से आते हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण दवाएँ शामिल हैं। प्राकृतिक व परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां का आधार हमारे विचार, खानपान और प्रकृतिमय जीवन है, जो बीमारियों को पनपने नहीं देता, यदि फिर भी कोई बीमारी आ जाती है उसका सस्ता, सरल, प्रभावी एवं सुगम इलाज पारम्परिक चिकित्सा पद्धति में है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

कुंभ में ईश्वर का आह्वान करतीं चेतनाएं.. तीर्थ पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे, सैकड़ों वर्षों तक

आचार्य रजनीश

इसमें कई बातें हैं। पहली बात जो समझ लेने की है, वह यह कि अगर कुंभ में देखें, तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। भीड़, निपट भीड़, जहां कोई चेहरा नहीं है। चेहरा बचेगा कहां इतनी भीड़ में? निपट भीड़ रह गई, फेसलेस। एक करोड़ आदमी इकट्ठा हैं। कौन राजा है, कौन रंक है, अब कोई मतलब नहीं रह गया। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई मतलब नहीं रह गया, फेसलेस हो गया सब। और ये एक करोड़ आदमी एक ही अभीप्सा से एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए हैं, एक ही प्रार्थना से, एक ही आकांक्षा से। इन सबकी चेतनाएं एक-दूसरे के भीतर प्रवाहित होनी शुरू होंगी। अगर एक करोड़ लोगों की चेतना का पूल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है, उतना आसान एक-एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। यह बड़ा कांटैक्ट फील्ड है। आदमी की चेतना कितना बड़ा कांटैक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है। क्योंकि वह इतनी बड़ी घटना है! उस बड़ी घटना के लिए, जितनी जगह हम बना सकें, उतनी उपयोगी है। इंडिविजुअल प्रेयर (व्यक्तिगत प्रार्थना) तो बहुत बाद में पैदा हुई। प्रार्थना का मूल रूप, तो समूहगत है। वैयक्तिक प्रार्थना तो तब पैदा हुई, जब एक-एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया। और किसी के साथ पूल-अप होना मुश्किल हो गया कि किसी के साथ हम एक हो जाएं। और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई, तब से प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हम जितना बड़ा क्षेत्र दे सकें, उसके अवतरण के लिए, उतना ही सुगम होगा। तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते हैं। फिर खास घड़ी में करते हैं, खास नक्षत्र में करते हैं, खास दिन पर करते हैं, खास वर्ष में करते हैं। वे सब सुनिश्चित विधियां थीं। इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियाडिकल है। जैसे कि वर्षा आती है, एक खास दिन पर आ जाती है। और अगर आज नहीं आती खास दिन पर, तो उसका कारण यह है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था, वह उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, वसंत आता था खास वक्त-सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। स्त्रियों का मासिक धर्म है, वह ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक अट्ठाइस दिन में उसे लौट आना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वह अट्ठाइस दिन में लौट आएगा। वह चांद के साथ यात्रा कर रहा है। वह अट्ठाइस दिन में नहीं लौटता, तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का, भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया, तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं। और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई, वह घड़ी जो है वह ज्यादा पोटेंशियल हो गई, उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः-पुनः उस घड़ी में तीर्थ पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे, सैकड़ों वर्षों तक।

राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना महज औपचारिकता नहीं

विवेक शुक्ला

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। देश इस बार गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। संयोग से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। वह भारत के मित्र होने के साथ-साथ एक करिश्माई नेता थे, जिन्होंने इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उन्हें बहुत सोच-विचार करने के बाद देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। उनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उड़ीसा (अब ओडिशा) के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और कई अन्य नेताओं से गहरे संबंध थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखा जाए, तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना, भारत और उस देश के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है।

गणतंत्र दिवस एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां भारत अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ सकता है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रख सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने का एक मंच है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति इस अवसर को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देती है। यह निमंत्रण सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा अवसर होता है, जब आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष भारतीय संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों को करीब से देख पाते हैं। एक बात और कि कभी-कभी यह एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष देश को आमंत्रित करना, उस देश के प्रति भारत के समर्थन या प्रशंसा का संकेत हो सकता है।

भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी के नेशनल स्टेडियम (अब ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम) में आयोजित किया गया था। पहले और 75 साल बाद फिर गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों का एक स्पष्ट प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर वार्षिक अतिथियों के क्रम में पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वह जब कर्तव्य पथ पर पधारे होंगे, तो उन्हें इंडिया गेट को देखकर अच्छा लगा होगा। कारण यह है कि इंडिया गेट और पेरिस में स्थित द आर्क डी ट्रायंफ में गजब की समानता है।

इंडिया गेट बना था प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में। वहां पर शहीदों के नाम भी अंकित हैं। द आर्क डी ट्रायंफ उन शहीदों की याद में बनाया गया था, जो फ्रांस के लिए विभिन्न जंगों में लड़े और अपनी जान दी। लगता है कि एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन बनाते हुए फ्रांस के सबसे बड़े प्रतीक द आर्क डी ट्रायंफ को गहराई से देखा होगा। यों तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमेरिकी राष्टपति बराक ओबामा से लेकर रूस के राष्टपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य अतिथि रहे हैं, पर दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति योद्धा नेल्सन मंडेला और महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का कर्तव्य पथ पर सबसे गर्मजोशी से उपस्थित अपार जनसमूह ने स्वागत किया था। मंडेला 1995 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। मंडेला जब परेड का आनंद ले रहे थे, तब वहां मौजूद दर्शक मंडेला के नारे लगा रहे थे।

गणतंत्र दिवस परेड का लंबे समय तक आंखों देखा हाल सुनाने वाले जसदेव सिंह बताते थे कि मंडेला की तरह कर्तव्य पथ पर उपस्थित अपार जनसमूह ने मुक्केबाज मोहम्मद अली का भी करतल ध्वनि से अभिनंदन किया था। वह 1978 के गणतंत्र दिवस समारोह में खास अतिथि थे। उस गणतंत्र दिवस समारोह में कहने को मुख्य अतिथि आयरलैंड के राष्ट्रपति प्रेट्रिक हिलेरी थे, पर सबकी निगाहें मोहम्मद अली को तलाश रही थीं। वह अपने चाहने वालों के अभिवादन का उत्तर अपने मुक्के को हवा में घुमाकर दे रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मोहम्मद अली को देखकर मुस्करा रही थीं।?बहरहाल, भारत आगे भी मित्र देशों के नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोहों में आमंत्रित करता रहेगा।

करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच स्वच्छता का हिमालय जैसा संकल्प

विनोद पाठक

वर्ष 2019 के कुंभ प्रयागराज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाईकर्मियों के पैर धोए थे और कहा था-सफाई कर्मियों के योगदान से कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई है, दिव्य कुंभ को भव्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का है% तो यह समाचार राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बना था। इस बार भी जब प्रधानमंत्री बीते 13 दिसंबर महाकुंभ प्रयागराज में संगम पूजन के लिए आए तो उन्होंने महाकुंभ जैसे दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका की चर्चा की थी।

विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में पहले दो प्रमुख स्नान बीत चुके हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद मेला क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था में कोई कमी नहीं देख रही है। गंगा, यमुना और संगम के न केवल घाट साफ-सुथरे दिख रहे हैं, बल्कि सड़कों पर 24 घंटे सफाई कर्मी स्वच्छता का विशेष ध्यान दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का विशेष फोकस महाकुंभ मेले में स्वच्छता को लेकर शुरुआत से रहा है। इसकी व्यापक तैयारियां पिछले कई महीनों से मेला क्षेत्र में देखी जा रही हैं। इस बार स्वच्छता को डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा गया है, ताकि 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मेला क्षेत्र में स्थापित 1.5 लाख शौचालयों की मॉनिटरिंग की जा सके। शौचालयों की सफाई में कोई कमी ना रहे, इसके लिए 2500 से अधिक गंगा सेवादूत मोबाइल के साथ तैनात हैं, जो बार कोड स्कैन के माध्यम से शौचालय की स्वच्छता और साफ- सफाई की व्यवस्था करते हैं। जेट स्प्रे से शौचालय तत्काल साफ हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए आईसीटी (इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव किया गया है।

मेल क्षेत्र में 15 हजार से अधिक सफाईकर्मी तैनात हैं। जब भी आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको जगह-जगह पर सफाई कर्मी झाड़ू लगाते, कचरा उठाते हैं और घाटों को साफ करते दिखेंगे। 40 कम्पेक्टर और 120 टिपर कूड़ा उठाने के लिए मेला क्षेत्र में दिन-रात दौड़ रहे हैं। 25 हजार से अधिक कचरा पात्र रखवाए गए हैं। गंगा, यमुना और संगम में दूषित पानी न जाए, इसको लेकर सरकार की व्यवस्थाएं सुदृढ़ नजर आती हैं। 200 किलोमीटर से लंबी ड्रेनेज लाइन डाली गई हैं। इसके अलावा, दो नए एफएसटीपी (फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट), तीन अस्थाई व 10 स्थाई एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सरकार ने लगाए हैं, ताकि जल निर्मल बना रहे।

सरकार ने सफाई कर्मियों के लिए स्वच्छ कुंभ कोष की भी स्थापना की, जिसमें 15 हजार सफाई कर्मियों के लिए बीमा, स्वास्थ्य समेत 6 योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। सफाई कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था (सेनिटेशन कॉलोनी), उनके बच्चों के लिए स्कूल (विद्या कुंभ) और आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा दी जा रही है। सफाई मित्रों को कोई आर्थिक दिक्कत न हो, इसके लिए प्रत्येक 15 दिन की अवधि में उनके खातों में धनराशि स्थानांतरित की जा रही है।

स्वच्छता से जुड़ा प्लास्टिक का भी बड़ा विषय है। इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। कुल्हड़, दोना-पत्तल और कपड़े व जूट थैला की दुकान सभी 25 सेक्टरों में खोली गई हैं। मेला में उपयोग में लाई गई प्रचार सामग्री भी प्लास्टिक मुक्त है। सरकार ने व्यापक स्तर पर प्लास्टिक उपयोग न करने को लेकर जन-जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियों को चलाया है। इस मुहिम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। संघ ने देशभर से 50 लाख स्टील की थाली और कपड़े के थैले इकट्ठा कर महाकुंभ क्षेत्र में भेजे हैं। अखाड़ों ने महाकुंभ मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु और देश-विदेश से पर्यटक आने वाले हैं। लोगों की इतनी बड़ा संख्या को देखते हुए स्वच्छ महाकुंभ का संकल्प हिमालय जैसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पहले दो प्रमुख स्नान के बाद निश्चित रूप से मेला प्रशासन अपनी तैयारियों का एक बार पुर्नावलोकन करेगा, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी, गंगा सेवादूत और मेला प्रशासन 4200 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को स्वच्छ और साफ बनाने में जुटा है, स्पष्ट है कि एक नया स्वच्छता का अनुभव देश-दुनिया से आकर पावन संगम में डुबकी लगाने वालों को मिल रहा है। महाकुंभ से एक बार फिर स्वच्छ भारत का संदेश देशभर में जाने वाला है।

शरणार्थियों के बोझ से कराहता मिजोरम

प्रभाकर मणि तिवारी

पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के बोझ से कराह रहा है। इससे स्थानीय आबादी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। मिजोरम पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा शरणार्थियों को रखने वाला राज्य है। यहां म्यांमार और बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी मिजोरम के करीब 50 हजार शरणार्थी रह रहे हैं। राज्य की आबादी करीब 11 लाख है यानी कुल आबादी का पांच फीसदी शरणार्थी हैं। अब भी सीमा पार से हर महीने सैकड़ों म्यांमारी शरणार्थी राज्य में पहुंचते हैं।

दूसरी ओर, राज्य सरकार अब तक म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा जुटाने का काम भी नहीं शुरू कर सकी है। केंद्र ने दिसंबर तक इस काम को पूरा करने की समयसीमा तय की थी। राज्य के 11 में से सात जिलों में बने करीब डेढ़ सौ राहत शिविरों में 40 हजार से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं। इनके अलावा हजारों शरणार्थियों ने राज्य में अपने रिश्तेदारों के घर शरण ली है। राज्य सरकार अब तक इन शरणार्थियों पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उसके अलावा कई गैर-सरकारी संगठन भी उनकी मदद करते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। राज्य सरकार के बार-बार अपील करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में शरणार्थियों में राशन बांटने के लिए पांच करोड़ की रकम भेजी है।

मिजोरम की 510 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगी है। वर्ष 2021 में वहां सैन्य तख्तापलट के बाद से ही सीमा पार से 30 हजार से ज्यादा शरणार्थियों ने पलायन कर मिजोरम में शरण ली है। सीमा के दोनों ओर चिन समुदाय के लोग ही रहते हैं और उनमें बेटी-रोटी का रिश्ता है। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी सीमावर्ती जिलों में बने राहत शिविरों में उनके रहने-खाने का इंतजाम किया है। उनके अलावा हजारों लोग इन इलाकों में बसे अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। पहले म्यांमार के साथ खुली सीमा नीति के तहत दोनों ओर के लोग बिना किसी कागजात के ही एक-दूसरे की सीमा में 16 किमी तक भीतर जा सकते थे लेकिन इस साल फरवरी में सरकार ने फ्री मूवमेंट रेजिम (एफएमआर) नामक उस समझौते को रद्द कर दिया। बावजूद इसके सीमा खुली होने की वजह से हर महीने सैकड़ों शरणार्थी जान बचाने के लिए मिजोरम पहुंच रहे हैं।

राज्य सरकार के अलावा सबसे ताकतवर सामाजिक संगठन यंग मिजो एसोसिएशन, चर्च और दूसरे संगठन उनकी मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार उनको शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकती लेकिन मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी शरणार्थी को राज्य से नहीं निकालेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र इनको शरणार्थी का दर्जा भले नहीं दे सकता, वह उनको राहत मुहैया कराने के लिए हमारी मदद के लिए सहमत हो गया है।

म्यांमार के अलावा कुछ महीने पहले बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय इलाके के करीब दो हजार शरणार्थी राज्य में पहुंचे थे। इसके साथ ही पड़ोसी मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद वहां से आने वाले कुकी जो जनजाति के दस हजार से ज्यादा शरणार्थियों ने महीनों से मिजोरम में शरण ली है।

केंद्र सरकार ने मिजोरम को म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा जुटाने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक यह काम शुरू नहीं हो सका है। राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बायोमेट्रिक आंकड़ों के लिए तैयार मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल म्यांमार के शरणार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह उन शरणार्थियों के लिए बना है जिनको उनके देश वापस भेजा जाना है। केंद्र ने राज्य सरकार को भरोसा दिया है कि म्यांमार में शांति बहाल नहीं होने तक इन शरणार्थियों को वहां वापस नहीं भेजा जाएगा।

राज्य सरकार के एक अधिकारी बताते हैं कि शरणार्थियों की बढ़ती तादाद से राज्य के खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा है। यह छोटा-सा पर्वतीय राज्य अपनी 80 फीसदी से ज्यादा वित्तीय जरूरतों के लिए केंद्र पर ही निर्भर है। इसके अलावा स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ रही है। इन शरणार्थियों में कई लोग सीमा पार से हथियारों और दूसरी अवैध वस्तुओं की तस्वीर में जुटे हैं। बीते दो-तीन वर्षों के आंकड़ों से साफ है कि शरणार्थी समस्या बढ़ने के साथ ही सीमा पार से तस्करी की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

हमें सुबह में ही गहरी नींद क्यों आती हैं ?

आप जानते हैं गहरी नींद में हमारी बॉडी टूट फूट मरम्मत करती है यह बॉडी को रिपेयर करती है सुबह की जो वायु होती है वह एक औषधि है।सुबह की ताजा वायु वर्कशॉप की तरह हमारे बॉडी को रिपेयर करती है आप जानते हैं हमारी बॉडी को प्रति क्षण, प्राणवायु चला रही है इसलिए सुबह की जो हवा होती है वह हमारी बॉडी के लिए औषधि का कार्य करती है। इसलिए गहरी नींद आती है ताकि हमारी बॉडी विधिवत टूट फूट मरम्मत और सफाई का कार्य कर सके, ताकि हम अगले दिन के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए तैयार हो सके ।

हमारी बॉडी सुबह ज्यादा रिपेयर करती है और जब गहरी नींद होती है उसी में यह कार्य विधिवत ढंग से हो पता है क्योंकि हमारा दिमाग ऑर्डर देता है हमारा दिमाग शांत होता है इसलिए इस तरह गहरी नींद आती है।

सुबह को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से सारी दुनिया जानती है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हमारी जो प्राण शक्ति है हमारे अंदर जो शक्ति है वही यह सब कार्य करती है हमारी बॉडी को रिपेयर करके अगले दिन के लिए तैयार करती है इसीलिए सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और इसीलिए गहरी नींद आती है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग रात्रि 8:00 के बाद खाना बनाना और खाना खाना शुरू करते हैं इनमें से कोई रात को 10:00 बजे खाता है कोई 11 या 12 बजे खाता है कितने लोग दो-दो बजे रात को खाते हैं आखिर बॉडी क्या करें ।

जो विधि है खाने की उसमें कहा जाता है कि सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक डिनर समाप्त हो जाना चाहिए ताकि बॉडी को पूरा खाना डाइजेस्ट करने का समय मिले और टूट-फूट मरम्मत और सफाई का समय मिले ताकि व्यक्ति सुबह 4:00 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्फूर्ति के साथ जाग जाए और

इन वजहों से जिद्दी बन जाता है बच्चा, आप भी रखें ध्यान

बच्चों का जिद्दी होना एक आम समस्या है, जिससे कई माता-पिता जूझते हैं। बचपन में अगर बच्चों की इस आदत पर ध्यान न दिया जाए, तो यह भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। बच्चों का व्यवहार उनके विकास, माहौल और परवरिश पर निर्भर करता है। बच्चों का जिद्दी स्वभाव उनके माहौल और परवरिश का परिणाम होता है। माता-पिता का धैर्य, समझ और प्यार बच्चे के व्यवहार को सुधारने में मदद कर सकता है। बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अनुशासन के महत्व को सिखाएं।

अत्यधिक लाड़-प्यार

जब बच्चे की हर बात मानी जाती है तो वह धीरे-धीरे जिद करने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जिद करने से उसकी हर मांग पूरी हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा बच्चों को छूट देने से भी वह जिद्दी हो जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वह बच्चों को अनुशासन का महत्व समझाएं। प्यार के साथ सीमाएं तय करें। साथ ही बच्चों की हर बात पर हां कहने के बजाए ना कहना भी सीखें।

माता-पिता की असहमति और मतभेद

अगर माता और पिता किसी बात पर एकमत नहीं होते और बच्चे के सामने एक-दूसरे की बात काटते हैं, तो बच्चा इस स्थिति का फायदा उठाकर जिद्दी बन सकता है। वह जैसा अपने अभिभावक के बीच जिद का स्तर देखता है, वैसा ही अपने जीवन में भी अपनाता है। माता-पिता को बच्चों के सामने एकजुट रहना चाहिए और एक जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

अत्यधिक प्रतिबंध और कठोरता

कुछ माता-पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतते हैं, जिससे बच्चे का स्वभाव जिद्दी हो जाता है। बच्चा सोचता है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए और जिद करनी होगी। हर बात पर बच्चे को नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से वह जिद्दी बन जाता है। माता-पिता को चाहिए कि वह प्यार और अनुशासन के बीच संतुलन बनाएं। कठोर होने की बजाय बच्चे को समझा कर चीजें सिखाएं।

बच्चे की भावनाओं की अनदेखी

जब बच्चे की भावनाओं और इच्छाओं को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, तो बच्चा जिद करना शुरू कर देता है। कई बार बच्चे माता-पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिद करते हैं। यह तब होता है जब माता-पिता बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अभिभावक बच्चे की भावनाओं को समझें, उनसे संवाद करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और रोजाना बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।

आपकी आंतों के लिए 'दुश्मन' जैसे हैं ये खाद्य पदार्थ

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन का ठीक रहना आवश्यक है और पाचन ठीक रहे इसके लिए जरूरी है कि आपकी आंतें ठीक तरीके से काम करती रहें। आंतें, भोजन को पचाने से लेकर मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने, भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में मदद करती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम बढ़ता जा रहा है, आंतों की सेहत पर भी इसका नकारात्मक असर हो रहा है।

आहार में गड़बड़ी के कारण आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पाचन विकारों का खतरा हो रहता है।आंतों में होने वाली समस्या के कारण थकान, पेट की खराबी, त्वचा की समस्याओं के साथ कई प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारियों का भी जोखिम हो सकता है। कहीं आपको भी आंतों की कोई दिक्कत तो नहीं है?

आंतों के लिए जरूरी हैं गुड बैक्टीरिया

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, वायरस और कवकों की लगभग 200 विभिन्न प्रजातियां होती हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं जबकि कुछ के अविश्वसनीय रूप से लाभ हो सकते हैं। शोध से संकेत मिलता है कि आंतों में पर्याप्त मात्रा में गुड बैक्टीरिया होने से पाचन विकारों के अलावा कई प्रकार की बीमारियों जैसे मधुमेह, इंफ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम (आईबीडी) की दिक्कतों से बचाव हो सकती है।

तले हुए और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ

आहार में कुछ प्रकार की चीजों, विशेषतौर पर तले हुए और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आंतों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ आंत संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं और पचान को कठिन बना सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थों की ही तरह से प्रोसेस्ड चीजों के सेवन के कारण भी आंतों और पाचन विकारों का खतरा हो सकता है। इन चीजों के अधिक सेवन के कारण कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों का भी जोखिम हो सकता है।

ज्यादा कैफीन भी आंतों के लिए हानिकारक

कैफीन के अधिक सेवन को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसके अधिक सेवन से आंतों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने से सीने में जलन, अपच और एसिड रिफ्लक्स जैसी पाचन संबंधी समस्याओं के बढ़ने का खतरा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ज्यादा कैफीन का सेवन करने से नींद विकारों की भी जोखिम हो सकता है।

रेड मीट के अधिक सेवन से करें बचाव

अध्ययनकर्ताओं ने बताया, रेड मीट वैसे को आयरन के सबसे बेहतर स्रोतों में से एक है, पर इसके नियमित या अधिक सेवन के कारण अपच की समस्या हो सकती है। यह आंत में बैक्टीरिया के विकास को भी ट्रिगर करता है, धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है और इसके अधिक सेवन से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। रेड मीट का अधिक सेवन करने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या भी अधिक हो सकती है, जो हृदय रोगों के प्रमुख कारकों में से एक है।

मेथी दानों को पानी में डालकर सुबह पिएं, सेहत को होंगे कई चमत्कारी लाभ

मेथी दाना सेहत की दृष्टि से बेहद गुणकारी है. ये छोटे-छोटे सुनहरे भूरे रंग के बीज कई रोगों से आपको सुरक्षित रखते हैं. मेथी में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, सोडियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी6 आदि होते हैं. मेथी दाना ब्रेस्टमिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है. टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करे. जब आप मेथी के दानों को पानी में रखकर उस पानी को पीते हैं तो ये भी डायबिटीज समेत कई समस्याओं में फायदेमंद साबित होता है.

इंडियनएक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार, मेथी के बीज बेहद ही पौष्टिक और सेहत के लिए लाभदायक होते हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वे इसका सेवन कर सकते हैं. मेथी के बीज वजन को तेजी से कम करने लिए जाने जाते हैं. हालांकि, मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका एक बार में अधिक सेवन करने से बचना चाहिए वरना पेट खराब हो सकता है. मेथी के दाने भूख को कम करते हैं और पेट भरे होने का अहसास कराते हैं. इससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं, जो वेट लॉस में मददगार होता है.

मेथी हाइपरग्लाइसेमिक सेटिंग्स के तहत इंसुलिन स्राव में सुधार कर सकती है और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ा सकती है. ऐसे में आप मेथी को पानी में भिगोकर खाएं या इस पानी का सेवन करें, हर तरह से लाभ होगा.

मेथी के दाने पीसीओएस या पीसीओडी में भी बेहतर हैं. साथ ही इसके सेवन से एनीमिया की समस्या दूर होती है. पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करती है. ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए, महिलाओं को पीरियड्स में होने वाले दर्द से राहत मिलता है. यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी दूर कर सकती है. आप इसे सब्जी में डालें, रोस्ट करके खाएं, पानी में डालकर भीगे मेथी खाएं या फिर मेथी वाला पानी पिएं. हर तरीके से मेथी का सेवन फायदा ही पहुंचाएगा.

यदि आपके बाल बहुत झड़ते हैं या रूसी की समस्या अधिक है तो मेथी बालों के लिए बेस्ट साबित हो सकती है. मेथी वाले पानी को रोज पीने से बाल स्वस्थ रहते हैं. डैंड्रफ की समस्या दूर होती है. आप मेथी वाले पानी से अपने बालों को शैम्पू करने के बाद धो भी सकते हैं.

मेथी के सेवन से या इसे पानी में डालकर इस पानी को पीने से पाचन शक्ति में भी सुधार होता है. डाइटरी फाइबर होने के कारण मेथी कब्ज की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है.

मेथी के बीज का ऐसे करें सेवन- एक से दो बड़े चम्मच मेथी दाने को एक गिलास पानी में डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. इस पानी में कैलोरी की मात्रा बिल्कुल नहीं है. ये एक बेहतर डिटॉक्स ड्रिंक है, जिसे सुबह खाली पेट पीना अधिक फायदेमंद होता है. साथ ही बचे हुए मेथी के बीजों को चबाकर खा जाएं, इन्हें फेंके नहीं.

पतली है आइब्रो तो घना करने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

आइब्रो को लेकर लड़कियां अक्सर परेशान रहती है क्योंकि अगर ये पतली हो तो इसका असर चेहरे की खूबसूरती पर पड़ता है। इस वजह से घनी आइब्रो को पसंद किया जाता है। हालांकि अगर आपकी भौहें घनी नहीं है तो इसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा सकती हैं।

नारियल का तेल लगाएं- नारियल तेल के फायदों के बारे में हम सभी जानते हैं। जो दरअसल यह बालों संबंधी कई समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। उसी तरह अगर आपकी आईब्रो पतली है तो आप नारियल का तेल लगा सकती है।

आप घनी भौंहों के लिए नारियल का तेल लगा सकती है

क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

कैसे करें इस्तेमाल- रूई को नारियल के तेल में भिगो लें। इसके बाद आईब्रो पर तेल को अच्छे से लगा लें। अब नारियल के तेल को रातभर आईब्रो पर लगा रहने दें। उसके बाद अगली सुबह फेश वॉश से अपना चेहरा साफ कर लें।

कैस्टर ऑयल से मिलेगा फायदा- सबसे पहले त्वचा को साफ पानी से क्लीन कर लें। अब इसके बाद उंगली पर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालें।

अब फिंगरटिप की मदद से आईब्रो को मसाज दें। अब कैस्टर ऑयल को आईब्रो पर आधे घंटे से ज्यादा देर तक न लगा रहने दें। इसके बाद इसे मेकअप रिमूवर की मदद से साफ कर लें।

इन बातों का रखे ध्यान-

* आंखों के आस-पास का एरिया बेहद सेंसिटिव होता है। तेल को आंखों के अंदर न जाने दें।

* अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो किसी भी चीज को लगाने से पहले पैच टेस्ट करना न भूलें।

राज कचौरी बनाने का आसान तरीका

ठंडे दही, चटनी एवं अनार के दानों से सजी स्वादिष्ट राज कचौरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। स्नैक्स में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टर में भी कई लोग राज कचौरी सर्व करना पसंद करते हैं। चाट के ठेले पर यह आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। स्ट्रीट फूड के रूप में बिकने वाली राज कचौरी को आप बहुत सरलता से अपनी रसोई में तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि।

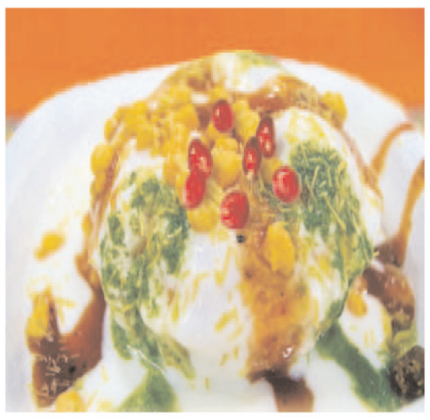

कचौरी के लिए जरूरी सामग्री

2 कप गेहूं का आटा,
आधा कप पिसी हुई चीनी,
आधा कप गुड़ की शक्कर,
1 कप देशी घी,
2 चम्मच बादाम गिरी,
2 चम्मच काजू गिरी,
आधा कप गोंद (भुना और दरदरा),
आधा कप मखाने (भुने और दरदरे),
1 चम्मच पिस्ता,
1 चांदी का वर्क,
2 चम्मच नारियल का चूरा,
1 चम्मच सोंठ.

राज कचौरी के लिए सामग्री

1 कप मूंग दाल
1 कप मैदा
1/4 कप सूजी
3 चुटकी बेकिंग सोडा
नमक स्वादअनुसार
1-2 हरी मिर्च, कटी हुई
1 इंच अदरक, बारीक कटा हुआ
1 छोटा चम्मच कटा हुआ ताजा हरा धनिया
एक चुटकी अजवाइन
एक चुटकी हल्दी पाउडर
1/4 छोटा चम्मच हींग

भराई के लिए सामग्री:-

1 बड़ा आलू, उबला और छिला हुआ
1 1/2 कप गाढ़ा दही
3 बड़े चम्मच पाउडर चीनी
नमक स्वादअनुसार
1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर
लाल मिर्च पाउडर छिड़कने के लिये
1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
1 चम्मच हरी चटनी
1 चम्मच इमली की चटनी
आधा कप अनार के दाने सजाने के लिए
1 कुरकुरी पापड़ी
सेव नमकीन 1 चम्मच
गार्निश के लिए ताजा हरा धनिया कटा हुआ

राज कचौरी बनाने की विधि:-

राज कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मूंग की दाल को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इतने में कचौरी का आटा तैयार कर लें। इसके लिए एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक एवं बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें। पानी की सहायता से सॉफ्ट आटा तैयार कर लें। अब इस आटे को 20 मिनट के लिए सेट होने रख दें।

साग-सब्जी काटकर धोएं या धोकर काटें

साग पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साग में कई तरह कंपोनेंट पाए जाते हैं। साग शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद है। अगर आप अपच की शिकायत, त्वचा संबंधी समस्याएं और अन्य मौसमी बीमारियों से राहत चाहते हैं तो हरा साग डेली डाइट में लें।

साग को पोषक तत्वों का एक पावरहाउस कहा जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर, विटामिन, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों से भरपूर है। आहार में हरा साग शामिल करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। न्यूट्रिशनिस्ट अमर देव यादव बता रहे हैं हरे साग बनाने का सही तरीका।

हरा साग धोकर काटें या काट कर धोएं, जानें सही तरीका

साग जब खरीद कर लाएं तो पहले इसकी जड़ काटें। इसके बाद साग को 4 से 5 बार पानी बदल-बदल कर अच्छे से धो लें और थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा रहने दें। साग से जब पानी निथर जाए तो इसे चाकू से बारीक काटें।

कभी भी साग काटने के बाद न धोएं। ऐसा करने से साग में मौजूद पोषक तत्व पानी के साथ निकल जाते हैं। कई बार साग खरीदते वक्त लोग मार्केट से कटवा लेते हैं ताकि दिक्कत न हो। लेकिन ऐसा साग केवल स्वाद के लिए खाया जा सकता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है।

हरे साग को ठीक ढंग से पकाने और खाने पर इसका पूरा पोषण मिलता है।

साग खाने का सही तरीका

साग को फ्राई करके सब्जी की तरह खाया जाता है। लेकिन इसे उबाल कर खाने पर ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन पालक को हल्का उबालें ताकि पोषक तत्व बर्बाद न हो। मेथी हरी सब्जियों को उबालकर खाने से आंखों की समस्या में लाभ मिलता है। साथ ही लें।

साग खरीदते समय यह ध्यान दें कि पालक का रंग प्राकृतिक रूप से हरा होना चाहिए।

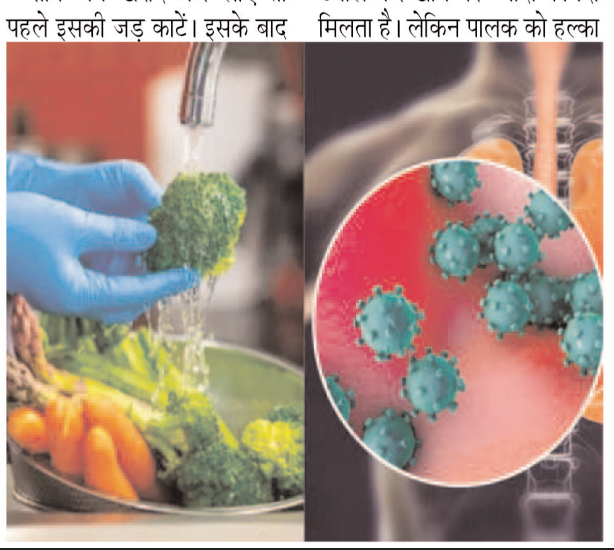

आपको कई रोग नहीं होते हैं।

फ्राई की हुई या उबली हुई सब्जी, क्या ज्यादा फायदेमंद

सब्जी को तेल में फ्राई करने पर इसमें फैट की मात्रा होती है जिससे कि फैट बढ़ता है। जबकि हाफ बॉयल सब्जियों में पोषण तत्व होते हैं। हल्की उबली सब्जी खाने से वेट कंट्रोल रहता है।

एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। खाना आसानी से पचता है। स्किन पर चमक आती है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है।

किस मात्रा में करें साग का सेवन

एक दिन में 1/2 कप उबला हुआ साग या 1 कप हरे साग का सेवन किया जा सकता है। लेकिन किसी डायटीशियन की सलाह जरूर ले

अगर साग से स्मेल आ रही है तो इसे ना खरीदें।

बहुत ज्यादा धूल-मिट्टी लगा साग न खरीदें, जड़ निकाला गया साग खरीदें।

जिस साग की पत्तियां ताजी लगे वही खरीदें।

साग को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें

साग के बंडल को खोल लें और फिर इसे एयरटाइट बैग में कर के फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। आप किचन में टोकरी में भी साग को खोलकर रख सकते हैं। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए इसे गीले कपड़े में लपेटकर भी रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी ने इसरो को ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पेडेक्स) परियोजना की सफलता भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो ने गुरुवार सुबह घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित सैटेलाइट डॉकिंग पूरी हो गई है, जिसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफल होने वाला चौथा देश बन गया है। पूरी टीम को बधाई! भारत को बधाई।

दिल्ली के लिए कांग्रेस की 3 नई गारंटी

नईदिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो वह शहरवासियों को 500 रुपये का एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। यह घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की, जो यहां एआईसीसी दिल्ली प्रभारी काजी निज़ामुद्दीन और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे, हमने वो सभी पूरा करने की कोशिश की है। इसी तरह हमने दिल्ली की जनता से भी जो वादे किए हैं, वो पूरा कर दिखाएंगे। 6 जनवरी को, कांग्रेस ने अपनी प्यारी दीदी योजना की घोषणा की, जिसमें सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपये का मासिक मौद्रिक अनुदान देने का वादा किया गया। 8 जनवरी को पार्टी ने अपनी जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत उसने 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया।

सीएम आतिशी और संजय सिंह को कोर्ट का नोटिस

नईदिल्ली। पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के जवाब में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अध्यक्षता वाली अदालत ने आप नेताओं से 27 जनवरी तक अपना जवाब देने का अनुरोध किया है। मानहानि की शिकायत एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आतिशी और सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है, जहां उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि दीक्षित को भाजपा से बड़ी मात्रा में धन मिला था। इसके अतिरिक्त, दीक्षित ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आप की चुनावी स्थिति को कमजोर करने के लिए भाजपा के साथ साझेदारी की है। संदीप दीक्षित वर्तमान में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। मामले को 27 जनवरी की समयसीमा के बाद आगे की विवेचना के लिए निर्धारित किया गया है।

दिल्ली चुनाव में हम आम आदमी पार्टी के साथ : अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। कांग्रेस को एक स्पष्ट संदेश में, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बजाय आप के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आप में नई दिल्ली में भाजपा को हराने की क्षमता है। यह स्वीकार करते हुए कि तृणमूल के भीतर अंदरूनी कलह थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कोई राजनीतिक दल विकास के दौर से गुजर रहा हो तो गुटबाजी एक स्वाभाविक लक्षण है। उन्होंने कहा कि जब हमने इंडिया ब्लॉक का गठन किया, तो हम एक निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हुए थे। हम सभी ने उस फैसले का समर्थन किया था। जो एक क्षेत्र में ताकतवर होगा, बाकी सभी पार्टियां उसका समर्थन करेंगी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ताकतवर है। इसलिए, कांग्रेस, सपा, आप, राकांपा और भारत के अन्य सभी गठबंधन सहयोगी राज्य में तृणमूल के साथ खड़े होंगे। क्षेत्रीय दलों के पक्षधर होने का यह सिद्धांत तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा इंडिया ब्लॉक की बैठकों के दौरान प्रस्तावित किया गया था।

फडणवीस सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना

मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार रात उनके मुंबई स्थित घर में चोरी के प्रयास के दौरान हुए जानलेवा हमले ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर राजनीतिक हमला शुरू कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं, तो मुंबई में कौन है। उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में जान से मारने की एक और हाई-प्रोफाइल कोशिश देखी गई, सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद है जो दर्शाता है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया है। चतुर्वेदी ने उस हमले का भी जिक्र किया जिसमें अनुभवी राजनेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हुई।

महू में होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली

राहुल गांधी समेत जुटेंगे पार्टी के सभी दिग्गज नेता

नईदिल्ली। बीआर अंबेडकर पर दिए गए बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली आयोजित करेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 27 जनवरी को महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर विभिन्न ब्लॉकों, जिलों और राज्यों में रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। महू रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

जयराम रमेश ने कहा कि 27 जनवरी को महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर विभिन्न ब्लॉकों,

जिलों और राज्यों में रैलियां आयोजित की जा रही हैं, उन्होंने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है।

महू रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को कांग्रेस के इस नए कार्यालय में सभी पीसीसी अध्यक्ष आएंगे, सभी महासचिव वहां होंगे, प्रभारी वहां होंगे और हम बेलगाम में पारित नव सत्याग्रह संकल्प प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे।

रमेश ने कहा कि वहां हमने घोषणा की थी कि यह वर्ष संगठन का वर्ष होगा। और हम 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक एक साल के लिए अलग-अलग राज्यों और जिलों में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कई विषयों पर बिना मतलब के ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है वह महात्मा गांधी का अपमान है और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस पर हमला है। मोहन भागवत को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए। ये राष्ट्रविरोधी है।

शाह ने गुजरात के वडनगर को दी 300 करोड़ की सौगात

- जनता को समर्पित किया पुरातत्व संग्रहालय

गांधीनगर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 298 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पीएम के गृहनगर वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने करीब 35 करोड़ से तैयार वडनगर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर एक फिल्म का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री ने वडनगर में विरासत परिसर विकास योजना, शहरी सड़क विकास और सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय 12,500 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। यह 2,500 साल से पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और निरंतर मानव निवास के क्रम को

उत्खनन किए गए पुरातात्विक प्रमाणों को दर्शाता है। यह भारत में विकसित अपनी तरह का पहला ऐसा संग्रहालय है, जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थल का अनुभव होगा। इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों, शंख निर्माण (उत्पाद और कच्चा माल), सिक्के, आभूषण, हथियार, औजार, मूर्तियां, खेल सामग्री तथा जैवक सामग्री जैसे खाद्यान्न, डीएनए और कंकाल अवशेषों से संबंधित लगभग 5,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। नौ विषयगत दीर्घाओं वाले इस संग्रहालय में 4,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में फैला उत्खनन स्थल है, जहां 12-16 मीटर की गहराई तक पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। इस उत्खनन स्थल पर एक अनुभवात्मक वॉक-वे शेड, आने वाले लोगों को उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का प्रदर्शन कराएगा।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर का उद्घाटन

गृह मंत्री शाह ने अहमदाबाद से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर %फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम% (एफटीआई-टीटीपी) का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने इससे पहले पिछले साल 22 जून को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल-3 से एफटीआई-टीटीपी का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करना है।

अरविंद केजरीवाल के हलफनामे पर भाजपा का सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की कुल संपत्ति 4.2 करोड़ रुपये घोषित की। 2020 में, केजरीवाल ने 3.4 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो 2015 से 1.3 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि थी। 2015 में केजरीवाल की कुल संपत्ति 2.1 करोड़ रुपये थी। चुनाव आयोग (ईसी) को सौंपे गए केजरीवाल के हलफनामे के अनुसार, केजरीवाल के पास कुल 3,46,849 रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें 50,000 रुपये नकद शामिल हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास 1,00,89,655 रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें 42,000 रुपये नकद शामिल हैं। उनकी अचल संपत्ति 1.7 करोड़ रुपये की है।

हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ कि केजरीवाल के पास कोई घर या कार नहीं है। हालांकि, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2014-15 से, अरविंद केजरीवाल अपने आय स्रोत को विधायक पारिश्रमिक के रूप में दिखाते हैं। बिना किसी अन्य स्रोत के 2020-21 में उनकी आय 40त्न कैसे बढ़ गई। ये पैसा कहां से आया? उन्होंने कहा कि 2020-21 वह समय था जब लोग कोविड के कारण घर पर थे, वे उस समय लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। उस समय आप और आपके शराब मंत्री दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की फरवरी 2023 में वेतन भत्ते वृद्धि से पूर्व में दिल्ली में तत्कालीन मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को 72,000 रूपए प्रति माह मिलता होगा जो वृद्धि के बाद 1,70,000 रूपए प्रति माह मिला होगा। इसी तरह जब वह पूर्व में 2014-15 में 7 माह सामान्य विधायक रहे तो उन्हे 55,000 रूपए का वेतन एवं भत्ते मिले होंगे। अब 17 सितम्बर 2015 के बाद से फिर उन्हे सामान्य विधायक का 90,000 रूपए वाला वेतन मिल रहा होगा। इस हिसाब से चलते हुए हम देखें तो अरविंद केजरीवाल के 2013-14 से 2024-25 तक की जो बेसिक बिना भत्ता आय भी बनती है वह उनके द्वारा कल 15 जनवरी 2025 को नामांकन पत्र दायर करते हुए जो हालफनामा दायर किया है उसमें दिए विवरण से मेल नही खाती।

उन्होंने कहा कि इस हिसाब से चलते हुए हम देखें तो अरविंद केजरीवाल के 2013-14 से 2024-25 तक की जो बेसिक बिना भत्ता आय भी बनती है वह उनके द्वारा कल 15 जनवरी 2025 को नामांकन पत्र दायर करते हुए जो हालफनामा दायर किया है उसमें दिए विवरण से मेल नही खाती।

बिहार चुनाव से पहले एक्शन में चिराग पासवान

पटना। अपराध और राजनीति अक्सर साथ-साथ चलते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ जब अयूब खान और रईस खान, जिन्हें खान बंधुओं के नाम से जाना जाता है, औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में शामिल हो गए। अयूब खान और रईस खान, जिनके नाम से एक समय पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आतंक फैला हुआ था, ने शुरू में नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि नीतीश ने उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी।

बुधवार को खान बंधुओं ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी (आरवी) की सदस्यता ली। सीवान के सहुली हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित मिलन समारोह के लिए खान बंधुओं ने पार्टी सुप्रीमो के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की थी। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि आज सिवान के साहुली हाई स्कूल में चिराग पासवान के प्रेरणादायक नेतृत्व में बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट और नव-संकल्प अभियान से प्रेरित होकर मो. अयूब खान और मो. रईस खान ने हजारों समर्थकों की उपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।

पार्टी ने लिखा कि उनका पार्टी में शामिल होना पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम में उमड़े विशाल जनसैलाब को संबोधित किया। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बुधवार को संकेत दिए कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अपने साथ जोड़ सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्टजे बाहर

जोहानिसबर्ग। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। नॉर्टजे ने जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। वह पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में वापसी करने वाले थे, लेकिन नेट्स में उनके पैर की अंगुली टूट गई। तब से वह अपनी स्न20 फ्रेंजाइजी, प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं खेले हैं और दक्षिण अफ्रीका के मार्की टी20 टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा करेगा।

वहीं एनरिक नॉर्टजे की जगह गेराल्ड कोएत्जी ले सकते हैं। वह पिछले नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ डरबन टेस्ट में कमर की चोट लगने के बाद जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए एक्शन में लौटे हैं। दक्षिण अफ्रीका के व्हाइट बॉल कोच रॉब वाल्टर ने बताया कि नॉर्टजे और कोएत्जी के बीच चयन को लेकर मुकाबला था और उन्होंने कोएत्जी के बजाय नॉर्टजे के अनुभव को चुना। उन्होंने ये भी संके दिए की उन्हें नॉर्टजे के फिट घोषित होने का पूरा भरोसा है। वाल्टर ने आगे कहा कि, एनरिक नॉर्टडे बेहतरीन गेंदबाज हैं। वह अपना और अपनी कंडीशनिंग का ख्याल रखते हैं। अपनी तरफ से मुझे उन पर भरोससा है और मुझे विश्वास है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होंगे। हालांकि, उनके इस बयान के 48 घंटे बाद दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नॉर्टजे का सोमवार दोपहर को स्कैन किया गया था और 50 ओवर के टूर्नामेंट के लिए समय पर उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, पिछले 6 आईसीसी आयोजनों में ये तीसरी बार है, जब एनरिक नॉर्टजे चोट के कारण बाहर हुए हैं और ये सभी वनडे टूर्नामेंट हैं। उन्हें 2019 वर्ल्ड कप में खेलना था, लेकिन टूर्नामेंट से पहले उनका अंगूठा टूट गया, अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 319 अंक चढ़ा निफ्टी 23,300 के पार

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार (16 जनवरी) को लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई और दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। अमेरिका में दिसंबर के दौरान महंगाई के नरम होने फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की खबरों से भी बाजार के सेंटीमेंट्स पर पॉजिटिव असर पड़ा है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गुरुवार (16 जनवरी) को 600 से ज्यादा अंकों की बढ़त लेकर 77,319 पर खुला। अंत में सेंसेक्स 318.74 अंक या 0.42% चढ़कर 77,042.82 पर बंद हुआ। इसी के साथ पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक रिकवर कर चुका है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी जोरदार तेजी के साथ 23,377.25 पर खुला। कारोबार के अंत में यह 98 अंक या 0.42% की बढ़त लेकर 23,311.80 पर क्लोज हुआ।

ग्रो एमएफ ने रेलवे पीएसयू थीम पर उतारे नए फंड

नईदिल्ली। रेलवे पीएसयू से जुड़े न्यू फंड ऑफर (एनएफओ)में निवेश करने का मौका है। एसेट मेनेजमेंट कंपनी ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ पेश किए हैं। यह ओपन-एंडेड स्कीम्स लॉन्ग टर्म में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इन दोनों फंड्स का एनएफओ में निवेश 16 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक खुला रहेगा। ये फंड निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, जिसमें रेलवे सेक्टर से जुड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शामिल हैं। ये कंपनियां रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में काम करती हैं। इन फंड्स के जरिए निवेशक रेलवे सेक्टर में हो रहे विकास का हिस्सा बन सकते हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस की तेल सप्लाई पर असर

नईदिल्ली। रूस की प्रमुख तेल कंपनियां Gazprom Neft और Surgutneftegas और उनके साथ जुड़े 183 रूसी क्रूड ऑयल जहाजों पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, वैश्विक बाजार में ओवरसप्लाई और अमेरिका सहित अन्य उत्पादक देशों से बढ़ती आपूर्ति के चलते भारत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। ओवरसप्लाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हो सकती है, जो फिलहाल 80 डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। यह भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की 88% जरूरतों को आयात के जरिए पूरा करता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पिछले शुक्रवार को रूसी कंपनियों और उनके तेल टैंकरों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से अधिकांश जहाज रूस से भारत और चीन को क्रूड सप्लाई कर रहे थे।

तिमाही के रिजल्ट के दम पर 11% भागा एचडीएफसी लाइफ

नईदिल्ली। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों में गुरुवार (16 जनवरी) को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी ने शेयर इंट्राडे ट्रेड में 11% तक चढ़ गए। इसकी तुलना में बीएसई सेंसेक्स 0.28% चढ़कर 76,942 पर कारोबार कर रहा था। कंपनी के शेयरों में उछाल तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद आया है। एचडीएफ़सी लाइफ ने बुधवार (15 जनवरी) को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। कंपनी का मुनाफा बाजार की उम्मीदों से ज्यादा रहा जिसकी असर कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रहा है। मजबूत तिमाही नतीजों को देखते हुए ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपडेट करते हुए एचडीएफसी लाइफ पर अपना टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। साथ ही स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह देते हुए 40% तक के अपसाइड रिटर्न का अनुमान जताया है।

ट्रंप का नया कार्यकाल और बजट निर्माण

(गतांक से आगे ...)

टी टी राम मोहन

आगामी बजट में हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि इन योजनाओं का नतीजा क्या रहा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि निजी क्षेत्र रोजगार निर्माण की सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरा होगा या फिर वह भविष्य में ऐसा करेगा। विनिर्माण अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है और निकट भविष्य में रोजगार निर्माण के लिए पूरी तरह इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। सेवा क्षेत्र रोजगार तैयार करता है, लेकिन उनमें से काफी रोजगार की गुणवत्ता बहुत खराब होती है।

शिक्षित बेरोजगारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए सरकार को खाली पद भरने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। उन सभी लोगों को वादे के मुताबिक 5,000 रुपये मासिक वृत्ति भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने सरकारी पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन किया लेकिन छह माह के भीतर इंटर्नशिप पाने में नाकाम रहे। सरकार के भीतर अनुत्पादक नौकरियों और मुफ्त उपहारों पर भी काफी चिंता जताई जाएगी। आलोचक कहेंगे कि सरकार को इसके बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर वृद्धि दर को 7 फीसदी के पार ले जाने में मदद मिलेगी।

हमने देखा है कि तेज वृद्धि से न तो अपने आप पर्याप्त रोजगार उत्पन्न होते हैं और न ही अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार आते हैं। भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही होता है। आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को राहत चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों अपने-अपने स्तर पर लोगों को मुफ्त सहायता दे रहे हैं, जिससे हम सार्वभौमिक

बुनियादी आय का भारतीय प्रारूप गढ़ रहे हैं। आपको पसंद हो या न हो समूचा राजनीतिक जगत तो इस पर एकमत है। अगर हम विपरीत वैश्विक हालात में भी जीडीपी वृद्धि को 6.5 फीसदी के इर्द-गिर्द रख सके तो निवेशक इसे भारत की बड़ी उपलब्धि मानेंगे। अंत में सरकार को सरकारी उपक्रमों, सरकारी बैंकों के प्रदर्शन के साथ शासन में भी सुधार करना होगा।

अब यह और भी जरूरी है क्योंकि निजीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) शीर्ष नियुक्तियों के लिए एक अच्छा मॉडल बनकर उभरा है। ब्यूरो में पेशेवर, रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि और वित्तीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होते हैं। यह वित्तीय संस्थानों के लिए पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी चेयरपर्सन की नियुक्ति करता है। सरकार उसकी सिफारिशों पर निर्णय लेती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का कम भी इस ब्यूरो को सौंप दिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने स्वतंत्र निदेशकों की जवाबदेही बढ़ा दी है। सरकारी बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को भी बढ़ाने की की आवश्यकता है। बैंक के आकार और प्रदर्शन के अनुसार इस पारिश्रमिक की अलग-अलग श्रेणी तय की जा सकती हैं।

वित्तीय क्षेत्र से बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यही काम करने वाले सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड को भी एफएसआईबी की तर्ज पर ही दोबारा गठित किए जाने की जरूरत है। इसे भी बेहतर शर्तों पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार होना चाहिए। सभी सरकारी उपक्रमों में बोर्ड के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक अलग पैनल बनाया जा सकता है।

करीब 6.5 फीसदी की वृद्धि दर का लक्ष्य, उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, रोजगार निर्माण पर बढ़ा हुआ सरकारी व्यय, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर शिथिलता और सरकारी उपक्रमों, सरकारी बैंकों के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देना आकर्षक तो कहीं से नहीं लगता। परंतु ट्रंप के आगमन के बाद बढ़ी अनिश्चितता में यही करने की जरूरत है।

कल्याणकारी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में बैंकों की है महत्वपूर्ण भूमिका

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बैंकिंग सिस्टमः वित्त मंत्री चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है। उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है। लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी।

समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह , प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक श्री सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड श्री ज्ञानेंद्र मणि, श्रीमती शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।

18 के बाद कभी भी हो सकती है छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणाः साव

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को बिलासपुर दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा संकेत दिया.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव तारीख की घोषणा जल्द- डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो गई है. नगरीय निकाय, जनपद से लेकर ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण का काम पूरा हो गया है. अब आगे का काम राज्य निर्वाचन आयोग को करना है.राज्य सरकार की तरफ से चुनाव का सारा काम कर लिया है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी घोषित की है. सरकार की मंशा है कि फरवरी में नगरीय व पंचायत चुनाव एक साथ कर लिये जाए.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

फरवरी में हो सकते हैं चुनाव- साव ने नगरीय निकाय चुनावों के साथ ही पंचायत चुनाव तारीखों के बारे में भी कहा. उन्होंने कि सरकार की इच्छा है कि नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव एक साथ करा लिया जाए. जिसके बारे में चुनाव आयोग को बता दिया गया है. उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हलके में हलचल तेज हो गई है.18 जनवरी को चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान- 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो रहा है. इससे पहले 15 जनवरी की तारीख तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया. 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है. इससे पहले बीते 6 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के कुल वोटरों की संख्या जारी की थी. इस सूची के अनुसार 1 जनवरी 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 2.11 करोड़ मतदाता है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता सूची की जानकारी दी थी.

रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी को सर्वाधिक पुरस्कार

मुख्यमंत्री साय एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा सिंह ने दी बधाई

रायपुर। इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 25वें रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में सीएसपीजीसीएल को एक श्रेणी में विजेता तथा 2 श्रेणियों में उप-विजेता का खिताब प्राप्त हुआ। विभिन्न श्रेणियों के लिए दिए गए लगभग 50 पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को मिला। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा, श्री सुबोध कुमार सिंह ने इन उपलब्धियों के लिए राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि सुशासन की अवधारणा को जमीनी हकीकत बनाने में कंपनी कर्मियों का योगदान सराहनीय है। यह सिलसिला नई उपलब्धियों के साथ लगातार जारी रहना चाहिए। श्री सुबोध सिंह के हाथों से जनरेशन कंपनी के एमडी श्री एसके कटियार ने पुरस्कार ग्रहण किया।

कर्नाटक राज्य के बेलगाम शहर में यह आयोजन 8 से 11 जनवरी के मध्य किया गया था। जिसमें देश के पॉवर सेक्टर में कार्यरत कई केंद्रीय एवं राज्य उपक्रमों के साथ ही विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रिट्रीट में 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में वैश्विक राजनीतिक समीकरणों, पानी अनाज और ऊर्जा के परस्पर संबंध, आपदा प्रबंधन, पॉवर सेक्टर एवं साइबर सिक्युरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाएं एवं चुनौतियां, 2047 तक विद्युत ऊर्जा के विकास की योजना आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारियां दी गई। रिट्रीट में 2023-24 के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न संवर्गों में पॉवर अवाड्र्स 2025 दिए गए। पारंपरिक स्रोतों से पॉवर जनरेशन में दो संवर्ग थे - 2012 के पूर्व स्थापित संयंत्र एवं 2012 के बाद स्थापित संयंत्र। वहीं 2012 के बाद स्थापित संयंत्रों के वर्ग में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम स्थित 500 मेगावॉट संयंत्र को फर्स्ट रनर-अप एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा को सेकंड रनर-अप के रूप में सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद ारा किया गया।

निःस्वार्थ कर्म से ही जीवन सफल होगाः टंक राम वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा तिल्दा विकासखंड के ग्राम सगुनी में निषाद समाज द्वारा आयोजित गुहाराम निषाद जयंती में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राम भक्त गुहा राज को नमन करते हुए कहा कि निःस्वार्थ कर्म ही जीवन को सद्गति दिला सकता है। रामायण के पात्र निषाद राज, शबरी, जटायु आदि के कार्यों से हमे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने सगुनी के निषाद समाज भवन के आहाता निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा खैरखूँट निषाद समाज भवन में शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राम के चरित्र को जीवन के सभी रुपों में देखा जा सकता है। भगवान श्रीराम ने मानव जीवन मे अनेक कार्यों से समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके आदर्शों को कोई भी आत्मसात कर समाज और जीवन को अच्छा बना सकता है। सफल जीवन के लिए निःस्वार्थ कर्म महत्वपूर्ण है। राम के भक्त और सेवक गुहा राज निःस्वार्थ कर्म करने के प्रेरणा स्त्रोत है।

लखमा ने भ्रष्टाचार को उजागर किया इसलिये ईडी ने उन पर कार्यवाही कियाः भूपेश बघेल

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी ने 2021-22 में कार्यवाही शुरू किया तीन साल बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। कवासी लखमा ने विधानसभा में विष्णु देव सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था इसलिये बदले की भावना में उन पर कार्यवाही किया गया। कवासी लखमा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार पर विधानसभा में सवाल पूछा था। तारांकित प्रश्न था, उसका लिखित जवाब भी आया, मंत्री ने खुद स्वीकार किया प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी उस समय बिना विभाग की स्वीकृति के बिना टेंडर के पुल निर्माण करवा लिया गया। टेंडर उस दिन खुला जिस दिन कवासी ने सवाल लगाया था। बिना टेंडर के बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय पुल बन रहा था। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार, दोषी अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय आठ दिन के भीतर ईडी ने कवासी लखमा और उनके परिवार के लोगों के यहां छापे मारे। छापे में कवासी लखमा यहां एक रुपया भी नहीं मिला और कोई कागजात भी नहीं मिला और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार और विष्णुदेव सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया और बात यही तक नहीं रूकी कुछ दिन पहले पत्रकार मुकेश चंद्रकार सड़क मामले को उजागर किया। सड़क की स्वीकृति जो 50 करोड़ की सड़क है और लागत बढ़कर 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं और 90 प्रतिशत भुगतान हो गया। तब पत्रकार की हत्या कर दी गई। मतलब यह है कि भ्रष्टाचार उजागर करेंगे तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी या मौत की नींद सुला दिया जायेगा यह स्थिति है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

लखमा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में कांग्रेस की बैठक

रायपुर। शराब घोटाला केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बुधवार देर रात दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कवासी की गिरफ्तारी, संगठन विस्तार और निकाय चुनाव पर मंत्रणा हुई।

गौरतलब है कि, पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कांग्रेस में हलचल मच गई। दिल्ली में देर रात कांग्रेस ने बड़ी बैठक ली। बैठक में दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत मौजूद रहे। ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम और फुलोदेवी नेताम भी शामिल हुए। तीनों प्रभारी सचिव भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए मुख्यालय में बैठक हुई।

सरकार परीक्षा और चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करें : दीपक बैज

रायपुर। सरकार परीक्षा और निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुये है। जबकि स्कूलों के बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं की समय सारणी घोषित हो चुकी है। दसवीं सीबीएससी की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी जो 18 मार्च तक चलेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की अन्य परीक्षाएं भी 1 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाली है। विभिन्न बोर्डों की घरेलू परीक्षाएं भी फरवरी माह में होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार तुरंत भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करती है तो भी चुनाव के नामांकन, प्रचार एवं मतदान का फरवरी के पहले होना संभव नहीं है। ऐसे में चुनाव एवं परीक्षाओं का टकराना निश्चित है। यह स्थिति भाजपा के डर के कारण आया है। सरकार चाहती तो अभी तक चुनाव संपन्न हो चुके होते और परीक्षाओं तथा चुनाव के बीच टकराहट नहीं होती। अब इस चुनाव के कारण बच्चों की परीक्षाये बाधित होगी।

हार के डर से घबराई भाजपा ईवीएम की शरण मेंः शुक्ला

रायपुर। हार के डर से घबराई भाजपा ईवीएम की शरण में पहुंच गयी है। नगरीय निकाय ईवीएम से कराने की अधिसूचना पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार चुनाव में हार से घबरा रही है। इसलिये ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। भाजपा को पता है कि बिना ईवीएम के वह कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। पहले स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा उसके बाद यू-टर्न लेकर नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय बताता है कि भाजपा चुनाव से घबरा रही है। ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला भाजपा के चुनावी डर के कारण आया है। भाजपा को प्रदेश की जमीनी हकीकत पता है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातावरण है। लोग प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण सरकार से निराश है, भाजपा की साय सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराश किया है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, एक साल में उसको पूरा नहीं किया है।

आरक्षण कटौती का फैसला वापस ले सरकारः वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रावधान में संशोधन करके दुर्भावना पूर्वक की गई कटौती वापस लेने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सामान्य सीटों पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का झूठा वादा करके भाजपा और साय सरकार ओबीसी विरोधी पाप से मुक्त नहीं हो सकती। ओबीसी वर्ग को उनके भागीदारी के अनुरूप आरक्षण का हक मिलना चाहिए, सरकार कुतर्क करके पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ़ थोपे गए निर्णय को जायज़ ठहराना बंद करे और ओबीसी आरक्षण विरोधी तुगलकी फरमान तत्काल वापस ले। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा के लोग जनता को गुमराह करना बंद करें। सामान्य सीटों पर प्रतिनिधित्व देने का वादा और ओबीसी समुदाय को उनकी आरक्षित सीटों का अधिकार दिए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। मुक्त सीटों पर किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रोक पाना संभव ही नहीं है जबकि आरक्षित सीट का मतलब केवल उस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करने से है, आखिर भाजपा को छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से इतनी हिकारत क्यों है।

वनवासियों को वनोपज का अधिक से अधिक लाभ मिलेः कश्यप

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा वनवासियों को वनोपज का अधिक से अधिक लाभ मिले यह सुनिश्चित की जा रही है। जंगल वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है इसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार 67 प्रकार के विभिन्न लघु वनोपज की खरीदी कर रही है और इसकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ताकि वनोपज खरीदी का अधिक से अधिक लाभ वनवासियों का मिल सके। यह बात वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज राजधानी स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण और अलंकरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि वन अतिक्रमण और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही.श्रीनिवास राव उपस्थित थे। वन मंत्री केदार कश्यप ने संघ के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष अजीत दुबे सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। वन मंत्री श्री कश्यप ने 45 उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति अधिकारियों का स्टार अलंकरण कर सम्मानित किया।

भूपेश बघेल ने आदिवासी नेता को यूज किया उससे उनकी आदिवासियों के प्रति सोच उजागर हुई

शराब घोटाले मामले में कानून मास्टरमाइंड तक भी जरूर पहुंचेगा : नबीन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पिछली कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की हुई गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक आदिवासी नेता को मोहरा बनाकर फँसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा था कि अपराध तो पूर्व आबकारी मंत्री द्वारा किया गया , लेकिन मास्टरमाइंड तो अभी पीछे बैठा है। श्री नबीन ने कहा कि कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकलेगा। मास्टरमाइंड कतई नहीं बचेगा।

भाजपा संगठन चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के सिलसिले में गुरुवार को राजधानी पहुँचे भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री नबीन ने विमानतल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बघेल ने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर शराब घोटाला किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी के प्रति बघेल की सोच क्या है और बघेल किस सोच के लिए जाने जाते हैं? बघेल यह अ%छी तरह समझ लें कि शराब घोटाले में संलिप्त कोई भी आरोपी बिल्कुल नहीं बचेगा, चाहे वह कोई भी हो। एक आदिवासी को बघेल ने मोहरा जरूर बनाया है लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। श्री नवीन ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध कहने पर भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 हजार करोड रुपए का शराब घोटाला कांग्रेस शासन के समय ही तो सामने आया था और केंद्रीय एजेंसियाँ कई बार तो उनके पास भी रही है। विभिन्न रा'य सरकारों में जाँच एजेंसियाँ रही हैं। डॉ रमन सिंह की सरकार जाने के बाद भूपेश बघेल खूब शेखी बघारते रहे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे; लेकिन 5 साल तक सरकार में रहते हुए वह क्यों कुछ नहीं कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं थे और आज तथ्य हैं, इसलिए घोटालों में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई हो रही है।

नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री नबीन ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मंडलों और जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की है और अब गुरुवार की शाम को नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश परिषद की घोषणा कल 17 जनवरी को होगी।

सरकार की अनदेखी पर फूटा कुर्मी समाज का गुस्सा

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदलने पर तीखा विरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम यथावत न रखने और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न देने पर कुर्मी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। समाज द्वारा लगातार किए जा रहे धरना-प्रदर्शन और विरोध के बावजूद सरकार की चुप्पी ने नाराजगी को और गहरा दिया है। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज ने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि समाज को हल्के में न लिया जाए।

नरदाहा के अंतराम बर्छिहा भवन में आयोजित केंद्रीय बैठक में समाज के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप ने कहा, सरकार ने समाज की भावनाओं की अनदेखी की है। यदि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा।

बैठक में आगामी महाधिवेशन की तैयारियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही सामाजिक सर्वेक्षण को प्राथमिकता से फरवरी तक पूरा करने का आग्रह राज प्रधानों से किया गया। समाज के आंतरिक प्रकरणों पर भी गंभीरता से चर्चा कर समाधान निकालने का निर्णय लिया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण न देने पर कुर्मी समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। समाज के नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज पिछड़ा वर्ग में शामिल है और पिछले चुनावों में 6 जिलों में आरक्षण मिला था, लेकिन इस बार पूरी तरह से अनदेखी कर समाज का अपमान किया गया है। केंद्रीय बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने एकजुट होकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.